न्यू देहली पोस्ट

■ वर्ष 13 ■ अंक 15 रविवार (साप्ताहिक) 20 अप्रैल 2025 ■ पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

फिर चर्चा में आई
हुमा कुरैशी

अंदर विशेष

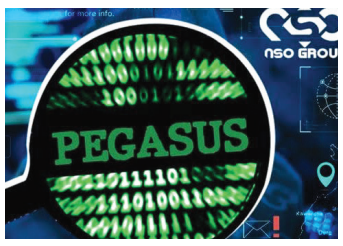

पेगासस का नया भूत : क्या झूठी है मोदी सरकार?
पृष्ठ 3 पर

फ़्रांस से भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान
पृष्ठ 5 पर

वक्फ बोर्ड के बाद कैथोलिक चर्च की बारी
पृष्ठ 7 पर

गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 21 दिनों की फरलो
पृष्ठ 10 पर

ओडिशा में पांडियन को लेकर बीजद में टूट की सम्भावना बढ़ी
पृष्ठ 11 पर

चीन -अमेरिका ताइवान को लेकर आमने -सामने
पृष्ठ 15 पर

मोदी के राज में शिवजी का

चाँद भी हो गया मुसलमान

2014 से इस काम की शुरुआत हो चुकी है। एक हद तक काम आगे भी बढ़ा है। आरपीएफ के हत्यारे जवान और मेहंदी लगाने वाले राजस्थानी युवक की मिसालें हमारे सामने हैं। और भी लाखों युवक-युवतियाँ होंगे, जिनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही नफरत की आग भभक रही है। आगे के वर्षों में वही आग करोड़ों हिंदू युवक-युवतियों के दिल में सुलगानी है। तभी बीजेपी पूरे भारत पर बिना बैसाखियों के एकछत्र राज कर सकेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संघ का सपना पूरा कर सकेगी।

नीरेंद्र नगर

नीचे तीन ख़बरों की सुर्ख़ियाँ हैं। आपको इन तीनों में से कौनसी सुर्ख़ी सबसे चिंताजनक लगती है?

पहली सुर्ख़ी- वक्फ क़ानून में संशोधन करने वाला बिल पिछले दिनों संसद से पास हो गया और राष्ट्रपति द्वारा उसपर मुहर लगाने के बाद संशोधित कानून 8 अप्रैल से लागू भी हो गया। दूसरी सुर्ख़ी- बागेश्वर धाम के मठाधीश ने ऐलान किया है कि वह ऐसी कॉलोनियाँ बसाएगा जिनमें केवल हिंदुओं को रहने की इजाजत होगी।और तीसरी यह कोई सुर्ख़ी नहीं है, क्योंकि यह किसी मीडिया में हाइलाइट नहीं हुई। यह केवल सोशल मीडिया पर आई है। ईद के अवसर पर मेहंदी लगाने वाले एक राजस्थानी युवक ने एक बुर्के वाले के साथ आई मुस्लिम लड़की के हाथों में मेहंदी लगाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह चाँद-वाँद नहीं बनाता।

इन तीनों में से कौन-सी ख़बर आपको सबसे भयानक लगती है? पहली, दूसरी या तीसरी? मेरी समझ से तीसरी। कारण, वक्फ कानून में संशोधन करने वाली बीजेपी सरकार आज है, कल नहीं भी हो सकती। वैसे भी अगर इसमें कुछ गैरकानूनी और असंवैधानिक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से वह फैसला पलट भी सकता है। बागेश्वर धाम का बाबा भी जो काम कर रहा है, उसका असर बहुत सीमित रहने वाला है। कोई भी नौकरी-धंधे वाला व्यक्ति अपना इलाक़ा छोड़कर उन हिंदू ग्रामों में रहने नहीं जा रहा। वैसे भी हर सोसाइटी और हर इलाके जहां हिंदुओं का बहुमत है, वे हिंदू सोसाइटी और हिंदू इलाके पहले से ही बन चुके हैं, खासकर शहरों में।

लेकिन तीसरी घटना अधिक डरावनी है। मेहंदी लगाने वाला वह युवक कोई धन्नासेठ नहीं है, न ही उसके पास कोई पक्की नौकरी है। फिर भी वह मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत के चलते चाँद बनाने से इनकार कर रहा है। यदि वह उस लड़की के हाथों में मेहँदी लगा देता, तो उसे कुछ आमदनी ही हो जाती। लेकिन मुसलमानों के प्रति उसके मन में जो घृणा है, वह इतनी अधिक है कि वह अपने रोजगार का नुकसान करने को भी तैयार है। वह यह भी नहीं सोच रहा कि चाँद न तो हिंदू है, न मुसलमान है। यह तो वही चाँद है जो उसके देवों के देव महादेव के सिर का ताज है। जब वह चांद किसी बुरका वाली के हाथ पर बनाया जाता है तो चाँद मुसलमान कैसे हो जाता है?

सबसे बड़ा खतरा ज़मीन पर है । उस युवक का व्यवहार यह बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हों, लेकिन ज़मीन पर उसका समर्थन कम नहीं हुआ है। यह घटना यह भी बताती है कि अपने जन्म के समय से स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन देश और समाज को हिंदू और ग़ैर-हिंदू में बांटने का जो प्रयास करते आ रहे हैं, उसका गहरा असर हो रहा है।

शेष १ पर

26 /11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पहुंचा तिहाड़ जेल
क्या होगी फांसी?

न्यूज़ डेस्क

आखिरकार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण इस बात का सबूत है कि भारत को टेढ़ी आंखों से देखने वाला कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में छिप नहीं सकता है। दुनिया को साफ संदेश है- भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर तक जाकर लड़ेगा। यह प्रत्यर्पण सिर्फ राणा की भारत वापसी नहीं है, यह उन 175 बेगुनाहों के परिजनों को न्याय देने की शुरुआत है, जिन्होंने 26/11 की रात अपनी जान गंवाई थी। भारत ने यह दिखा दिया कि चाहे आतंकी कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर किसी भी आका का हाथ क्यों नहीं हो, आज न कल उसे भारतीय न्याय व्यवस्था का सामना करना ही पड़ेगा।

तो तहव्वुर राणा भारत में पहुँच गया है। भारत ने उसे दिनों भारी सुरक्षा घेरे में अमेरिका से दिल्ली लाया और उसे क़ानूनी कार्रवाई के बाद तिहार जेल में बंद कर दिया। अब उस पर मुकदमा चलेगा। जांच होगी। सच उगलवाया जाएगा और पाकिस्तान के खेल भी किया जाएगा। संभव है कि भारतीय कानून व्यवस्था के तहत उसे फांसी की सजा भी दी जाए। भारत के लोगों की भी यही मांग है और किसी भी दुर्दांत आतंकी इससे कम सजा क्या हो सकती है।

इस्लामिक स्कॉलर मुफ़्ती वजाहत काजमी न्यू दिल्ली ;पोस्ट से बात करते हुए साफ़ तौर से कहा है कि ''हालाँकि तहव्वुर राणा एक छोटी मछली है फिर भी इसने भारत के खिलाफ काम किया है और इसे मोदी सरकार को फांसी देनी चाहिए ताकि भारतीयों का दिल ठंढा हो सके। इसे अब सबक सिखाने की जरुरत है ताकि दुनिया के किसी भी आतंकी को पता चले कि भारत के खिलाफ जाने का कितना भयानक दंड हो सकता है। इसके बाद कोई भी आतंकी भारत के खिलाफ आँख भी नहीं उठा सकेगा।

शेष १ पर

'ऑपरेशन धनवर्षा' का काला सच
कुंवारी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा फिर रेप....?

न्यू देहली पोस्ट

उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ समय से सुर्ख़ियों में है। पहले इस जिला की ज्यादा जानकारी देश के बाकी इलाके को शायद ही होगी। लेकिन साल भर से इस जिले की कहानी देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा में है। कभी इस जिले से कई हिंसक वारदातों की कहानी सामने आती है तो कभी हिन्दू -मुसलमान से जुड़े स्थलों की कहानी चर्चित होती है। लेकिन आज कल संभल एक ऐसे गिरोह के लिए चर्चा में है जो गरीब लड़कियों को करोड़पति बनाने के नाम पर उसे अपनी चपेट में लेता था और फिर उसे तिलस्मी संसार में ले जाकर रेप को अंजाम देता है। गिरोह से जुड़े अपराधी इस खेल को धनवर्षा कहते थे । यह

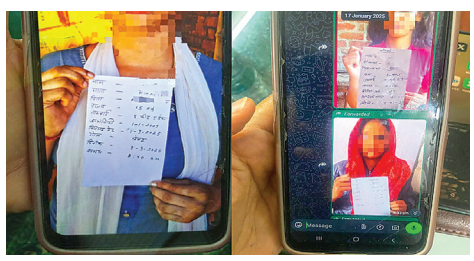

गैंग कथित तौर पर तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को 'करोड़पति' बनाने का दावा करता था और अपने जाल में फंसाकर लड़कियों का यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग करता था।

अंधविश्वास की अंधी गलियों में छुपा है एक ऐसा काला सच जहां गरीबी को मजबूरी और मासूमियत को साधन बना लिया गया है। अमीरी के लालच में फंसे गरीबों को सपने दिखाए जाते हैं, तंत्र-मंत्र से बदलती तकदीर के बारे में। लेकिन उस तकदीर की कीमत होती है कुंवारी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की विशेष पूजा और बाद में वह सब जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। धनवर्षा के नाम पर ये तांत्रिक और ढोंगी बाबा कुंवारी लड़कियों को आवेदन फार्म के माध्यम ऐसे बीस सवालों के ऐसे जवाब भरने को कहते थे जिसे जान कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लड़की को अपना नाम भरना होता था। पिता का नाम भरना था अपनी जन्मतिथि भरनी थी और उसमें यह भी लिखना होता था कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट की लंबाई कितनी है। फार्म में यह भी भरना होता कि उसको पीरियड कब आते हैं और कब उसके पीरियड खत्म होते हैं। साथ ही उसमें यह भरना होता था कि उसने पिछले 15 दिनों में किसी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं।

शेष १ पर

मोदी के राज में शिवजी...

2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 2009 के 19% से बढ़कर 2014 में 31% हो गया था, तो कई राजनीतिक विश्लेषक इस पहेली को सुलझाने में लग गए कि इन 31% वोटरों में कितने लोग वे हैं, जिन्होंने गुजरात दंगों के बाद बनी मोदी की हिंदू हृदय सम्राट की छवि के चलते बीजेपी को समर्थन दिया है, कितनों ने मोदी की ओबीसी पहचान के चलते पार्टी का हाथ थामा है और कितनों ने मोदी के गुजरात छाप विकास के दावों के चलते कमल का बटन दबाया है।

यह सवाल महत्वपूर्ण था और आज भी है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में एक और जरूरी प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ था कि मोदी के नेतृत्व में क्या भारत भविष्य में धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा।

इस प्रश्न का सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी का सारा-का-सारा वोटर कम्युनल नहीं है और यह बात बीजेपी भी जानती है कि जिन ओबीसी वोटरों ने मोदी के ओबीसी होने के चलते पार्टी को वोट दिया है, वे कल किसी विरोधी पार्टी के ओबीसी नेता के पक्ष में भी जा सकते हैं। इसी तरह 2022 तक हर बेघर व्यक्ति के सर पर छत और किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा टूटने के बाद कई किसान और बेघर लोग किसी और सपनों के सौदागर के पीछे भी चलने लग सकते हैं। इसीलिए पार्टी की कोशिश है कि वे वोटर, जो मोदी की ओबीसी पहचान या विकास के वादों के चलते, पार्टी की तरफ़ खिंचे चले आए थे, उन्हें हिंदुत्व के ऐसे नशे का आदी कर दिया जाए कि उनके लिए रोज़ी-रोटी के मसले छोटे हो जाएँ और हिंदुत्व का झंडा उठाना और मुसलमानों को सबक सिखाना सबसे जरूरी और पहला काम हो जाए। इसीलिए 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही गौरक्षकों के नाम पर हर गली, हर गाँव में गेरुआ गुंडों की फौज तैयार होने लगी। किसी भी मीट को गोमांस बताकर मुसलमानों की हत्या होने लगीं। मेनस्ट्रीम टीवी मुसलमानों के विरुद्ध भड़काऊ प्रचार और सोशल मीडिया पर मुसलमानों को राक्षस साबित करने वाले फर्जी वीडियो शेयर किए जाने लगे। नतीजे में दंगे हुए तो उसमें भी मुसलमान ही मारे गए और मुसलमान ही गिरफ़्तार भी हुए क्योंकि पुलिस जो पहले भी हिंदुत्ववादी थी, मोदी सरकार के आने के बाद उसे खुली छूट मिल गई। उधर यूपी में योगी के शासन में आने के बाद "बुलडोज़री" इंसाफ शुरू हो गया, जिसे बाद में दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकार ने भी अपनाया। इस इंसाफ़ के चलते जिस भी मुसलमान पर कोई आरोप लगा, शासन द्वारा उसका घर गिरा दिया गया।

अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार और संघ से जुड़े संगठनों द्वारा की गई इन कोशिशों का ज़मीन पर कितना असर हुआ है, इसकी पहली पड़ताल 2019 में होनी थी, लेकिन तभी बारामुला हो गया और जब चुनाव आया तो यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि बीजेपी के पक्ष में 6% की जो बढ़ोतरी हुई थी (31% से बढ़कर 37%), उसका कारण क्या था? पाँच सालों का मुस्लिम-विरोधी दुष्प्रचार? मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सुपरिणाम? या पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के कारण उभरा देशभक्ति का उफान?

कारण चाहे जो रहा हो, 2019 में अपने वोटों और सीटों में इजाफे के बाद मोदी और शाह और अधिक निरंकुश हो गए। कश्मीर से 370 हटाया, सीएएए का कानून बनाया, अयोध्या पर अपने अनुकूल फ़ैसला जुटाने वाले चीफ जस्टिस को सांसद बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्रतिष्ठा का ज़बरदस्त प्लान भी बनाया। इसके साथ-साथ में ज़मीन पर भयंकर एंटी-मुस्लिम प्रचार भी चलता रहा जिसका एक घिनौना परिणाम तब दिखा, जब जुलाई 2023 में आरपीएफ के एक जवान ने मोदी और योगी की जय-जयकार करते हुए एक ट्रेन में चुन-चुनकर तीन मुसलमानों को गोली मार दी। उसके बाद 2024 का चुनाव आया। संघ और बीजेपी को राम मंदिर और अपने अन्य प्रयासों से 400 पार जाने की उम्मीद थी लेकिन वे घटकर 240 पर आ गए। कई लोगों को लगा कि बीजेपी और संघ का हिंदुत्ववादी अजेंडा अपनी धार खो रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण अपनी अंतिम सीमा पर जाकर रुक चुका है।लेकिन यह भ्रांत धारणा थी, क्योंकि सीटें कम होने के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर उतना ही था जितना कि 2019 में था यानी 37%। तार्किक बात तो यह थी कि 2019 में बीजेपी के वोट शेयर में जो 6% का उफान आया था, उसको यदि सर्जिकल स्ट्राइक का असर माना जाए तो 2024 में उस उफान को नीचे आना चाहिए था, खासकर इसलिए कि इंडिया ब्लॉक इस दफ़ा पूरी ताक़त के साथ लड़ा था। ऐसे में बीजेपी का समर्थन कम-से-कम 2014 के लेवल तक आ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं आया। बीजेपी का वोट शेयर 2019 के बराबर ही रहा यानी क़रीब 37%।

संघ परिवार और बीजेपी के लिए यह ख़ुशी की बात थी कि 2024 के बाद से उसके समर्थकों की संख्या बढ़ी ही है, घटी नहीं है।लेकिन उनके लिए चिंता की बात यह थी कि यह केवल केंद्र में हो रहा था। राज्यों में हिंदुत्व या मोदी का जादू नहीं चल रहा था। वहाँ बीजेपी का सपोर्ट घट-बढ़ रहा था। जो वोटर लोकसभा में मोदी और बीजेपी को वोट कर रहा था, उसका एक हिस्सा विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को वोट दे रहा था जिसका सीधा-सीधा मतलब यह था कि लोकसभा में बीजेपी को वोट देने वाला हर वोटर कट्टरपंथी नहीं था। वह फ्री बिजली या फ्री बस सेवा के लिए या पिछली बीजेपी सरकार के कामकाज से नाराज़ होकर विपक्षियों को सत्ता सौंपने को तैयार था। 2015 में सबसे पहले यह कारनामा दिल्ली में दिखा। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखा और 2023 में कर्नाटक में दिखा।

यह संघ और पार्टी के लिए चिंता की बात थी। राज्यों के चुनावों में हिंदुत्व का झुनझुना काम नहीं कर रहा था। परंतु इसका इलाज क्या हो? बीजेपी और संघ बहुत ही शातिर और चालाक संगठन हैं। अगर अपने काम की बात हो तो वे दुश्मनों से भी सीख लेते हैं। यहाँ भी यही हुआ। राज्यों के चुनाव जीतने के लिए उसी औज़ार का सहारा लिया गया, जिसका इस्तेमाल ममता बनर्जी की सरकार ने 2021 के विधानसभा चुनाव में किया था। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी लक्ष्मी भंडार के नाम से एक योजना लागू की थी, जिसके तहत महिलाओं को हर माह 500 से 1000 की रकम दी जाती थी। इस योजना के चलते भ्रष्टाचार के तमाम आरोप झेलने के बावजूद 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने अपने पिछले प्रदर्शन के मुक़ाबले में 3% की बढ़ोतरी कर रिकॉर्ड जीत हासिल की। फिलहाल यह राशि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1000 और अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के लिए 1200 है। हो सकता है, अगले साल होने वाले चुनावों से पहले इसे डबल कर दिया जाए।

बीजेपी ने 2023 के चुनावी वर्ष में यही प्रयोग मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के नाम से शुरू किया जिसका उसे सफल परिणाम मिला। पिछले साल यही प्रयोग हरियाणा और महाराष्ट्र में किया गया और वहाँ भी उसे दोबारा सत्ता मिली। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र - इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने विपक्षी सरकारों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई थीं। इस नाते दोनों राज्यों में उसको नुकसान होना चाहिए था। लेकिन दोनों राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन के पक्ष में क़रीब 7% वोटों की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में भी बीजेपी ग़रीब महिलाओं को हर महीने ढाई हज़ार रुपये देने का वादा करके 26 सालों के बाद सत्ता में आई। वोट शेयर में भी उसका पिछले चुनाव के मुकाबले क़रीब 6% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देने के इस फ़ॉर्म्युले ने बीजेपी को ही लाभ नहीं पहुँचाया। इसका जादू झारखंड में भी दिखा, जहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने वोट शेयर में तक़रीबन 8% की ही बढ़ोतरी के साथ फिर सत्ता में आया। वहाँ भी सोरेन ने मैया सम्मान के नाम से ऐसी ही योजना चलाई हुई थी। जब अलग-अलग राज्यों में तकरीबन एक जैसे नतीजे दिख रहे हैं - सत्तारूढ़ दल के पक्ष में 6-7-8% की बढ़ोतरी - तो यह मानना ही पड़ेगा कि ग़रीब महिलाओं को मासिक रक़म देने की योजना हर राज्य में अपना पॉजिटिव असर दिखा रही है। इससे यह भी पता चलता है कि जनता के एक वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सरकार ईमानदारी से बनी है या बेईमानी से, वह अच्छा काम कर रही है या नहीं। बस, उसे आप "कैश" देने की व्यवस्था कर दो, तो वह आँख मूँदकर आपको वोट दे देगा और इससे आपके समर्थन में 6-7-8% का इज़ाफ़ा हो जाता है।

हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली - इन तीन राज्यों में एक ही फ़ॉर्म्युला अपनाकर हासिल की गई जीतों से बीजेपी को एक रामबाण नुस्ख़ा मिल गया है, जिसकी मदद से वह भविष्य में उन सभी राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है, जहाँ अभी विपक्ष की सरकारें हैं। काम बहुत आसान है। सबसे पहले विपक्षी विधायकों को तोड़ना है, अपनी सरकार बनवानी है, अगले चुनावों में महिलाओं के लिए सरकारी ख़ज़ाना खोलना है। फिर चुनाव में जीतकर वापस आना तय है। कभी चाल-चरित्र और चिंतन की बात करने वाली बीजेपी आज येन-केन-प्रकारेण हर राज्य की सत्ता हासिल करना चाहती है। क्यों? इसलिए क्योंकि वह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्यों दोनों में सत्ता में रहेगी, तभी संघ और उसके सहयोगी संगठन देश भर में हिंदू एकीकरण और मुस्लिम दानवीकरण का अपना अपना काम मुस्तैदी से जारी रख सकेंगे।

2014 से इस काम की शुरुआत हो चुकी है। एक हद तक काम आगे भी बढ़ा है। आरपीएफ के हत्यारे जवान और मेहंदी लगाने वाले राजस्थानी युवक की मिसालें हमारे सामने हैं। और भी लाखों युवक-युवतियाँ होंगे, जिनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ही नफरत की आग भभक रही है। आगे के वर्षों में वही आग करोड़ों हिंदू युवक-युवतियों के दिल में सुलगानी है। तभी बीजेपी पूरे भारत पर बिना बैसाखियों के एकछत्र राज कर सकेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संघ का सपना पूरा कर सकेगी।

कुंवारी लड़कियों के...

इस तरह के लगभग 20 सवाल होते और इन 20 सवालों की जानकारी उस फॉर्म में जो कि व्हाट्सअप पर एक मैसेज था उसमें अपलोड करने होते थे। फॉर्म को अपलोड कर दिया जाता है और फिर उस जानकारी को गिरोह अपने आका के पास भेज देता था। अब बस इंतजार होता कि अब धन वर्षा होगी। बहुत सारा पैसा होगा गरीबी दूर हो जाएगी। ये इंतजार ऐसा होता जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। धनवर्षा के इन्तजार में गरीब लड़कियों और महिलाओं की इज्जत तार -तार हो जाती थी। यह एक अंतहीन खेल था और इस खेल में न जाने कितनी लडकियां गिरोह का शिकार हो रही थी। लड़कियों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया जा रहा था और उनको एक ऐसी जगह ले जाकर उनके साथ विशेष पूजा के नाम पर तंत्र-मंत्र किया जा रहा था। लेकिन अब इस गंदे खेल का भंडाफोड़ हो गया है।

आइए हम आपको बताते है कि आखिर कैसे हुए इस गंदे खेल का खुलासा। दरअसल, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस को 21 मार्च को थाना धनारी क्षेत्र के गांव बमनपुरी के रहने वाले राजपाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी मां की कमर में दर्द था। 11 मार्च को वह मां का तंत्र मंत्र से इलाज करवाने के लिए गांव के ही लाखन व रिंकू से मिला था। पुलिस के अनुसार, लाखन गिरोह का सरगना है। इसके बाद लाखन, रिंकू, अजय सिंह व दुर्जन, राजपाल को नरौरा ले गए। जहां वह लोग एटा से संतोष व शिवम के साथ जबरन आगरा में अज्ञात जगह पर ले गए। वहां से जैसे तैसे निकलकर दो दिन बाद राजपाल अपने घर पहुंचा और पुलिस को पूरे इस गंदे खेल की जानकारी दी।

मामले में थाना पुलिस ने बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जब नामजद रिंकू, अजय, संतोष, दुर्जन आदि से पूछताछ की गई और उनके मोबाइल खंगाले गए तो पाया गया कि ये सभी अभियुक्त अंतरराज्यीय धनवर्षा ठगी गिरोह के सदस्य हैं। ये तंत्र क्रिया के माध्यम से धन वर्षा (नोटों की बारिश) का झांसा देकर भोले भाले गरीब परिवार की लड़कियों व लड़कों की तस्करी कर यौन शोषण करते हैं और वन्य जीव की तस्करी भी करते हैं। इस मामले में 28 मार्च को पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया। आइए अब आपको बताते है कि कैसे यह गिरोह फंसाते थे गरीब लोगों को। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य झांसा देते वक्त कहते थे कि.तंत्र क्रिया के लिए युवती कुंवारी हो, लंबाई 5 फीट 5 इंच से अधिक, शरीर पर कोई कटे-जले व टैटू गोदना का निशान नहीं हो , कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो और किसी जानवर ने काटा नहीं हो। . गिरोह के लोग गरीब परिवार को निशाना बनाते थे और उन्हें प्रलोभन देते थे कि उनकी लड़की विशेष गुण संपन्न है, जिस पर तंत्र क्रिया करने से घर में नोटों की बारिश होगी।

इतना ही नहीं पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि तंत्र क्रिया करने से पहले लड़की का वीडियो बनवाया जाता था। लड़की के हाथ में एक कागज देकर फोटो खींची जाती थी। इसके अलावा अन्य चीजें भी देखी जाती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्य लड़की को गुरु के पास लेकर जाते थे, जो एकांत में लड़की पर तंत्र क्रिया का नाटक करता था और तंत्र क्रिया के दौरान लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती थी।

इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अंधविश्वास, गरीबी और लालच का जब गंदा मेल होता है, तो सबसे ज्यादा शिकार होती हैं मासूम बेटियां । यह कोई साधारण ठगी नहीं, यह एक संगठित अपराध था – जिसमें तंत्र-मंत्र की आड़ में यौन शोषण, मानव तस्करी, और वन्य जीवों की तस्करी जैसे जघन्य कृत्य छिपे थे। भले ही इस गिरोह के कुछ लोग पकडे गए हैं लेकिन यह कौन जानता है कि यह गिरोह और कहाँ -कहाँ किस रूप में संचालित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता और कड़ी विवेचना ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है – क्या ऐसे गिरोह सिर्फ एक जिले में हैं? क्या बाकी जगहों पर भी इसी तरह की "धनवर्षा" की स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही?एक सवाल यह भी है कि संभल के जिस इलाके में यह गिरोह काम कर रहा था वहां की पुलिस ख़ुफ़िया को यह सब कैसे पता नहीं नहीं चल सका। क्योंकि यह खेल कोई एक दिन का नहीं था। यह सब सालों से चल रहा था।

ऐसे में समाज को अब जागने की ज़रूरत है।माता-पिता को ज़रूरत है कि वे लालच और अंधविश्वास के जाल को पहचानें। युवाओं को ज़रूरत है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रहे ऐसे मैसेज को आँख मूँदकर न मानें। और प्रशासन को ज़रूरत है कि वह ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई करे ताकि कोई बेटी ऐसे गिरोह का शिकार न बने।

26 /11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर...

मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है ऐसे में भारत के खिलाफ जो जाएगा उसे भारत के कानून के मुताबिक दंडित तो किया ही जाना चाहिए। इस राणा ने हमारी जमीन पर हमला किया है। '' 17 साल पीछे चलें तो 26 नवंबर, 2008 की रात भारत के इतिहास की सबसे भयावह रातों में से एक थी। मुंबई की गलियों में गोलियों की गूंज, बम धमाकों की आवाजें और बेगुनाहों की चीखें... इन सबके पीछे जो नाम था, वो आज एक बार फिर सुर्खियों में है- तहव्वुर हुसैन राणा। अब वही राणा भारत की जमीन पर वापस लाया गया है। उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाने में मोदी सरकार का संकल्प का जाहिर होता है। राणा को अमेरिका से भारत लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था बल्कि कई स्तर पर कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना ठान लेने पर क्या नहीं मिलता। भारत को राणा भी मिल गया। इसके लिए भारत सरकार के दो मंत्रालयों के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों ने तालमेल का शानदार उदाहरण पेश किया। अब एक खास फ्लाइट से राणा की दिल्ली में लैंडिंग हुई और इसके साथ ही भारत की आतंकवाद के खिलाफ जंग को एक बड़ी जीत मिली है। राणा की भारत वापस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का परिणाम नहीं है बल्कि यह भारत की दृढ़ता, तैयारी और विदेश नीति की ताकत की कहानी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर अमेरिका की एजेंसियों के साथ महीनों तक संपर्क और समन्वय किया। अमेरिका के न्याय विभाग की मदद से यह मिशन पूरा हुआ। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एनआईए ने एनएसजी समेत खुफिया एजेंसियों के साथ भी जबरदस्त काम किया।

राणा की भारत वापसी में सबसे बड़ा रोड़ा था अमेरिका का न्याय तंत्र। आतंकी तहव्वुर राणा की कानूनी टीम ने अमेरिकी अदालत में यह तर्क दिया कि उसे पहले भी कुछ अपराधों के लिए सजा मिल चुकी है, इसलिए उसे फिर से भारत में सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन भारतीय कानून विशेषज्ञों ने अमेरिका की अदालत में यह साबित कर दिया कि भारत में उस पर यूएपीए के तहत अलग आरोप हैं। यह तर्क अमेरिकी कोर्ट और न्याय विभाग को इतना मजबूत लगा कि राणा की हर अपील को खारिज कर दिया गया।

अमेरिकी अदालत में राणा ने भारत आने से बचने के लिए यहां की जेलों और पुलिस व्यवस्था की कमियां बताईं। उसने कहा कि भारत की जेलें सुरक्षित नहीं हैं और उचित सुविधाएं भी नहीं। उसने दावा किया कि भारत की पुलिस मानवाधिकार का ख्याल नहीं रखतीं और पूछताछ के नाम पर कैदियों पर अत्याचार करती हैं। इस पर भारत ने अमेरिका को यह भरोसा दिया कि राणा को जेल में सुरक्षा दी जाएगी, उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं होगा और सिर्फ उन्हीं आरोपों में उस पर मुकदमा चलेगा जिनके लिए प्रत्यर्पण हुआ है।

यह मामला सिर्फ अदालत में जीता नहीं गया बल्कि भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। भारत की लगातार कोशिशों और विश्व मंच पर मजबूत छवि के चलते अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण को जल्दी मंजूरी दी। उधर, अमेरिका में सरकार का बदलना भी भारत के काम आया। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार दूसरी बार संभाला। ट्रंप प्रशासन भी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने को इच्छुक था और भारत को सफलता मिली। 64 साल का राणा कभी पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। बाद में वह कनाडा चला गया और वहां का नागरिक बन गया। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ-साथ लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। उसने आईएसआई और आतंकी संगठनों की प्लानिंग पर ही मुंबई में 26/11 अटैक की पूरी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया। उसने अटैक से पहले भारत आकर रेकी भी की थी। तहव्वुर राणा को अमेरिका में 18 अक्टूबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया था। उसे शिकागो में संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से उसे लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था।

26 नवंबर, 2008 की वो रात भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी थीं। 175 मासूम लोगों की जान चली गई थी। होटल ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन जैसे इलाके आतंक का गवाह बने थे। उस हमले में शामिल नौ आतंकी तो मारे गए थे, लेकिन मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 नवंबर, 2012 को फांसी दी गई थी।

न्यू देहली पोस्ट
14-20 अप्रैल 2025
संपादकीय कार्यालय : मुद्रक व प्रकाशक आशीष कुमार द्वारा विभा पब्लिकेशन डी-160 बी, सेक्टर-7, नोएडा से मुद्रित एवं 262ए, सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद से प्रकाशित। RNI NO. UPHIN/2013/49239
संपादक : आशीष कुमार, **प्रसार प्रबंधक** : दशरथ सिंह
Postal registration Number: UP/GBD-181/2013-15, **हमसे संपर्क करें** : postnewdelhi@gmail.com

संपादकीय

विचारहीन राजनीति के प्रतीक नीतीश और चंद्रबाबू

मुसलमानों के साथ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी। कोई कह सकता है कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है ? कोई सेक्युलर चेहरा पाखंड से लबरेज धार्मिक राजनीति का समर्थन कैसे कर सकता है ? ऐसे में तो या तो जो सेक्युलर चेहरे हैं वे पाखंडी हैं और अपनी कुर्सी और राजनीति को सहेजने के लिए वे वही सब कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। देश की राजनीति को टटोलने पर मौजूदा समय में दो ऐसे चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बीजेपी के साथ वह सब करते दिख रहे हैं जिसकी इजाजत इस सेक्युलर जमात नहीं देता। आज भले ही ये दोनों नेता सत्ता की कुर्सी से चिपके रहे ,आगे भी ये सत्ता में बने रहे लेकिन देश की राजनीतिक इतिहास में इनके नामों की चर्चा हमेशा पाखंडी ,धोखेबाज पलटीमार नेता के रूप में ही होती रहेगी। यह बात और है कि जब हमारी अगली पीढ़ी ऐसे नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे और गलियां तक देंगे तब हम इसे सुनने और देखने के लिए शायद जीवित नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और आँध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बारे में। इन दोनों नेताओं ने अभी हाल में विपक्ष और मुस्लिम समाज के तमाम विरोध के बाद भी वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार का साथ दिया और इस बिल को पास कराने में महती भूमिका निभाई। वैसे इस बिल को पास कराने में कई और दल और उसके नेता भी शामिल रहे लेकिन इन दोनों बैदे नेताओं की चर्चा इसलिए की है क्योंकि इन्ही के सपोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है। ये दोनों नेता आज चाहे तो यह सरकार गिर सकती है और मोदी -शाह की पूरी राजनीति ख़राब हो सकती है लेकिन ऐसा हुआ कहाँ ? सरकार गिराने की बात तो दूर ,इन दोनों नेताओं ने तो सरकार को और मजबूत करने का काम किया। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन देकर इन्होने यह जाता दिया है कि ये पाखंडी सेक्युलर रहे हैं। इनकी असलियत तो यही है कि ये किसी के नहीं है। जहाँ सत्ता की कुर्सी मिले और जो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाए ,वही इनके आका है। नीतीश कुमार की अगली राजनीति क्या होगी ,उनको फिर से सत्ता मिलेगी या नहीं ,उनकी पार्टी टूट जाएगी और बीजेपी के साथ मर्ज भी कर जाएगी इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का मुस्लिम समाज की नजरों में नीतीश कुमार एक ऐसे विलेन के रूप में प्रकट हुए हैं जिसे कभी यह मुस्लिम जमात वोट देकर यह मान लेता था कि यह नेता मुसलमानों की रक्षा करेगा और देश में चल रही धार्मिक उन्मादी राजनीति से उसे बचाएगा। नीतीश कुमार केवल राजनीतिक पाला ही नहीं बदले हैं। इन्होने अपने विचार को भी बदल लिया है। उन्होंने जो किया है वह विचारहीन राजनीति का पराकाष्ठा है। नीतीश कुमार से यह पूछा जाना चाहिए कि जब 2013 में मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार घोषित हुए तो वे एनडीए से अलग क्यों हुए थे ? उन्होंने कहा था कि वे साम्प्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रह सकते। वे खुद सेक्युलर गढ़ को आगे बढ़ाएंगे और साम्प्रदायिक ताकतों को हराएंगे। जब मोदी ने सद्भावना यात्रा के दौरान टोपी पहनने से इंकार किया था तब तो नीतीश ने पलटवार करते हुए कहा था कि देश चलाने के लिए सभी को साथ लेकर चला जरुरी है। कभी टोपी भी पहननी होगी तो कभी तिलक भी लगाना होगा। नीतीश आज कहाँ खड़े हैं इसके बारे में कौन पूछ सकता है ? और इसका जवाब कौन देगा ? अभी दो साल पहले ही नीतीश इंडिया गठबंधन के अगुआ बने थे और बार बार साम्प्रदायिक ताकतों को हटाने की बात करते थे लेकिन आज वे उसी बीजेपी की गोद में बैठे हैं। नेताओं के चरित्र का इतना बड़ा हनन किसने कहाँ देखा है ?

नीतीश यह भी जानते हैं कि बीजेपी उनका उपयोग चुनाव तक करना चाहती है। नीतीश यह भी जानते हैं कि बिहार के अगले चुनाव में कुछ भी संभव है। वे यह भी जानते हैं कि उनकी पार्टी बिखर चुकी है और उनके नेता उनसे अलग होकर बीजेपी के साथ जा बैठे हैं। लेकिन वे दसब इसलिए सहते जा रहे हैं कि कहीं फिर से मौका मिल जाए। क्या यह संभव है ? और जहाँ तक चंद्रबाबू की बात है वे तो पहले से ही चालक रहे हैं। एनडीए और मोर्चा सरकार के समय में भी वे अपना लाभ ले रहे थे। उनका मकसद यही रहा है कि किसी का सपोर्ट करके अपनी राजनीति को मजबूत किया जाए और आंध्रप्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल की जाए। लेकिन पिछले चुनाव में जब उनकी पार्टी को बड़ी जीत हुई और उस जीत में मुसलमानो के योगदान को वे कैसे भूल गए ? राजनीति अगर पतित है तो इन नेताओं को किस विशेषण से संबोधित किया जा सकता है ? वक्फ बिल पर समर्थन देकर चंद्रबाबू ने जो अपराध किया है उसे आंध्रा की जनता भी सहन नहीं कर पा रही है।

पेगासस का नया भूत : क्या झूठी है मोदी सरकार ?

अखिलेश अखिल

पेगासस जासूसी का नया प्रमाणिक भूत फिर से सामने आ गया है। चार अप्रैल के अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में पेगासस ख़ुफ़िया यंत्र बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने एक बड़ी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की है जिसमे कहा गया है कि भारत में सौ लोगों की जासूसी कराई गई। एनएसओ के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत के किसी भी मीडिया घराने में इस खबर को अभी तक नहीं छापा है और न ही किसी टीवी चैनल ने इस खबर को दिखाने का काम किया है। यह आजाद भारत के मीडिया का एक ऐसा सच है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इतनी बड़ी खबर को छुपाने के पीछे का सच यही है कि मोदी सरकार को बदनाम होने से बचाया जाए। मौजूदा समय के भारतीय मीडिया को मोदी मीडिया कहा जाए तो इसमें कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी।

बता दें कि अमेरिकी अदालत में व्हाट्सअप ने एनएसओ के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। व्हाट्सअप का कहना है कि इजरायली कंपनी ने उसके ग्राहकों की निजता का हनन किया है जो एक आपराधिक कृत्य है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यह मामला भारत में 2019 से ही चल रहा है और हर बार मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी होने से इंकार करती रही है। तब देश के करीब सौ से ज्यादा लोगों जिनमे बड़े पत्रकार राजनेता और विपक्षी नेताओं ने इसकी शिकायत सरकार से की थी। देश में हुआ गठा। कई दिनों तक संसद भी बाधित हुआ था। जांच कमेटी भी बनी थी लेकिन उस जांच कमिटी की रिपोर्ट भी आज गटक सामने नहीं आई। सरकार देश हित और सुरक्षा का मामला बताते हुए कुछ भी बताने से इंकार कर दिया था। यह भी बता दें कि इज़ायक पेगासस जासूसी यंत्र को किसी आम या ख़ास लोगों को नहीं बेचता है। इसकी डीलिंग सरकार और उसकी एजेंसियों से होती है। ऐसे में अगर भारत सरकार ने इस यंत्र की खरीददारी की है ,जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है तो जाहिर है कि भारत के जिन सौ लोगों की जासूसी की गई है वह सरकार के इशारे पर ही की गई है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या फिर एनएसओ झूठ फैला रहा है। आखिर झूठा कौन है ?

अमेरिकी अदालत में एनएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा व्हाट्सएप हैकिंग के शिकार लोगों वाला देश मेक्सिको है, जिसमें ऐसे 456 लोग हैं। भारत 100 के साथ दूसरे नंबर पर है। 2019 में, रिपोर्टों में कहा गया था कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार को सूचित किया था कि 121 भारतीय उपयोगकर्ता पेगासस द्वारा लक्षित थे। व्हाट्सएप द्वारा भारत सरकार को यह बताए जाने के छह साल बाद कि 121 भारतीय उपयोगकर्ता इजरायली स्पाइवेयर पेगासस द्वारा लक्षित थे, मैलवेयर निर्माता एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अपने मुकदमे में प्रदर्शित नए दस्तावेजों में कहा गया है कि 100 भारतीय प्रभावित हुए थे।दस्तावेज में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर पेगासस से प्रभावित लोगों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप हैकिंग के शिकार लोगों वाला देश मेक्सिको है, जिसमें ऐसे 456 लोग हैं। गौरतलब है कि मार्क जुकरबर्ग के मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने 2019 में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। 2024 के अंत में, एक

अमेरिकी अदालत में एनएसओ ने स्वीकारा कि सौ भारतीयों पर जासूसी कराई गई

अमेरिकी जिला अदालत ने मुकदमे में एनएसओ ग्रुप को उत्तरदायी पाया। इधर 4 अप्रैल को प्रकाशित दस्तावेज़ दुनिया भर में पेगासस पीड़ितों के स्थान के बारे में पहली जानकारी है। इसमें 51 देशों में 1,223 विशिष्ट पीड़ितों को दर्ज किया गया है। मेक्सिको (456) और भारत (100) के बाद, बहरीन (82), मोरक्को (60), पाकिस्तान (58), इंडोनेशिया (54) और इज़राइल (51) हैं।

बता दें कि पेगासस एक परिष्कृत स्पाइवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा एक भी लिंक पर क्लिक किए बिना फोन को संक्रमित कर सकता है।2021 में, द वायर समाचार आउटलेट्स के एक अंतरराष्ट्रीय संघ में से एक था, जिसने संभावित निगरानी की एक लीक सूची की मदद से पेगासस के उपयोग का खुलासा किया था। एनएसओ समूह का कहना है कि यह केवल "जांच की गई सरकारों" को अपना स्पाइवेयर प्रदान करता है। 2021 की समाचार जांच के दौरान, कंपनी ने अपने ग्राहकों की सूची सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में इन रिपोर्ट में किए गए निष्कर्षों की जांच का आदेश दिया था। इसके द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने पाँच फ़ोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह नहीं बता पाई कि यह पेगासस था या नहीं। पूछे जाने पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया कि उसने पेगासस हासिल किया था और उसका इस्तेमाल किया था।

इज़राइली टेक साइट सी टेक, जिसने सबसे पहले व्हाट्सएप के देश-वार नंबरों की रिपोर्ट की,और यह भी कहा कि सूची में किसी देश के शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि वह एनएसओ का क्लाइंट था। उदाहरण के लिए, सीरिया में 11 पीड़ितों की सूची है - जबकि यह एक ऐसा देश है, जिसे एनएसओ को पेगासस बेचने से प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें तीसरे देशों या खुफिया सेवाओं द्वारा लक्षित किया गया हो सकता है।" हालांकि, जिन लोगों को लक्षित करने के लिए चुना गया है - विपक्षी राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं जैसे लोगों से दृढ़ता से पता चलता है कि भारतीय नंबरों पर स्पाइवेयर संचालित करने वाली एजेंसी आधिकारिक भारतीय हो सकती है। लेकिन बात वही है कि मोदी सरकार इस मसले पर अब तक मौन क्यों है ? क्या सरकार ने जासूसी नहीं कराई ? और नहीं कराई तो उसे सामने आना चाहिए। या फिर एनएसओ झूठ बोल रहा है और भारत सरकार को बदनाम कराने को तैयार है ?

वक्फ कानून पर देशभर में बवाल, कही आगजनी तो कहीं हाथापाई

न्यूज़ डेस्क

वक्फ संशोधन कानून लोकसभा-राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है। इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। तारीख अभी नहीं तय की है। लेकिन इस बीच देश भर में इस कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। इस कानून के खिलाफ जहाँ जम्मू कश्मीर विधान सभा में विधायकों के बीच हाथापाई की खबरे भी है। उधर पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कोंके सहारे पर उतर गए हैं। मणिपुर में इस कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी है। कई घरों में आग लगाने की खबरे भी आ रही है। जानकारी के मुताबिक़ मणिपूर में एक बीजेपी नेता के घर में भी आग लगाने की रही है। बिहार में मुस्लिम समाज के लोग काफी नाराज हैं और वह जदयू ,लोजपा जैसी पार्टियों को रसातल में भेजने की नात कर रहा है तो यूपी के मुसलमान और धार्मिक नेता वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के केरल और आंध्रा प्रदेश से भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की खबरे मिल रही है और चंद्रबाबू नायडू से नाराज लोग अब उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। बिहार मढे जहाँ नीतीश कुमार को सबक सिखाने का ऐलान मुस्लिम समाज कर रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी से दर्जनों मुस्लिम नेता निकल गए हैं और कहा जा रहा है कि जयंत की राजनीति ख़त्म हो सकती है। जयंत अभी तक जाट और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के सहारे आगे बढ़ते रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी।ममता कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा-कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर

धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूं। मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी। चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो यही हमारा रास्ता है। इस बयान पर भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता फर्जी हिंदू हैं, अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया। फिर भी ममता चुप हैं। इधर, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को लगातार तीसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।दूसरी ओर, आप विधायक मेहराज मलिक ने कहा- हिंदू तिलक लगाते हैं लेकिन पाप करते हैं। इस पर भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने मलिक की निंदा करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का अपमान है। एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी।

उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते मंगलवार शाम को वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई। कई वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगी दी। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसे प्री प्लान्ड हिंसा बताया। मणिपुर के थोउबल जिले में भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके बाद असगर अली ने सोशल मीडिया पोस्ट में माफी मांगी थी और कानून वापस लेने की मांग की थी। वक्फ संशोधन बिल को पास होने के बाद से अब तक सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए वक्फ कानून को लेकर कहा है कि '' 2013 का वक्फ कानून मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश थी। नया वक्फ कानून सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम है। 2013 में कांग्रेस सरकार की ओर से लाया गया वक्फ कानून मुस्लिम कट्टरपंथियों और लैंड माफिया को खुश करने की कोशिश थी वक्फ को लेकर बहस की जड़ तुष्टिकरण की राजनीति है।'' सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 याचिकाएं दर्ज नए वक्फ कानून की संवैधानिकता के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल तक 12 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में कानून को चुनौती देंगी। वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी।सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम लेटर्स और मेल देखने के बाद फैसला करेंगे। इसकी लिस्टिंग करेंगे।

वक्फ संशोधन कानून 'उम्मीद' से जगी सुधार की उम्मीद

संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, २०२५ को बीते शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई।

न्यूज़ डेस्क

संसद सत्र के अंतिम सप्ताह में वक्फ संशोधन विधेयक एक दिन के अंतराल पर संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। यह बात और है कि इस बिल को पास कराने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों ने देर रात तक संसद में बहस की। आरोप -प्रत्यारोप के दौर चले लेकिन अंत यही हुआ कि दोनों सदनों में यह बिल पास हो गया। अब विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आस की एक उम्मीद बची हुई है। शीर्ष अदालत आगे क्या कुछ फैसला लेती है और यह तो देखा जाएगा लेकिन बड़ी तेजी से दोनों सदनों से पास इस बिल पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी मुहर लगा दी है। बड़ी बात यह है कि इस कानून का नाम भी दाल दिया गया है। अब यह कानून 'उम्मीद अधिनियम 1995 ' नाम से जाना जाएगा। उम्मीद अधिनियम 1995 का पूरा नाम है -यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट ,इम्पावरमेंट ,एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (यानी उम्मीद) अधिनियम 1995.कानून।

संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को बीते शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को तड़के और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को तड़के इसे मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे जबकि ऊपरी सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति मुर्मु के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उचित उपयोग को लेकर नई दिशा मिलेगी। इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

बता दें कि इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार, और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन बताया गया है। विरोध के कारणों में मुस्लिम समुदाय और विपक्ष का मानना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति को हस्तक्षेप माना जा रहा है। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में कहा कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि करोड़ों गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा।

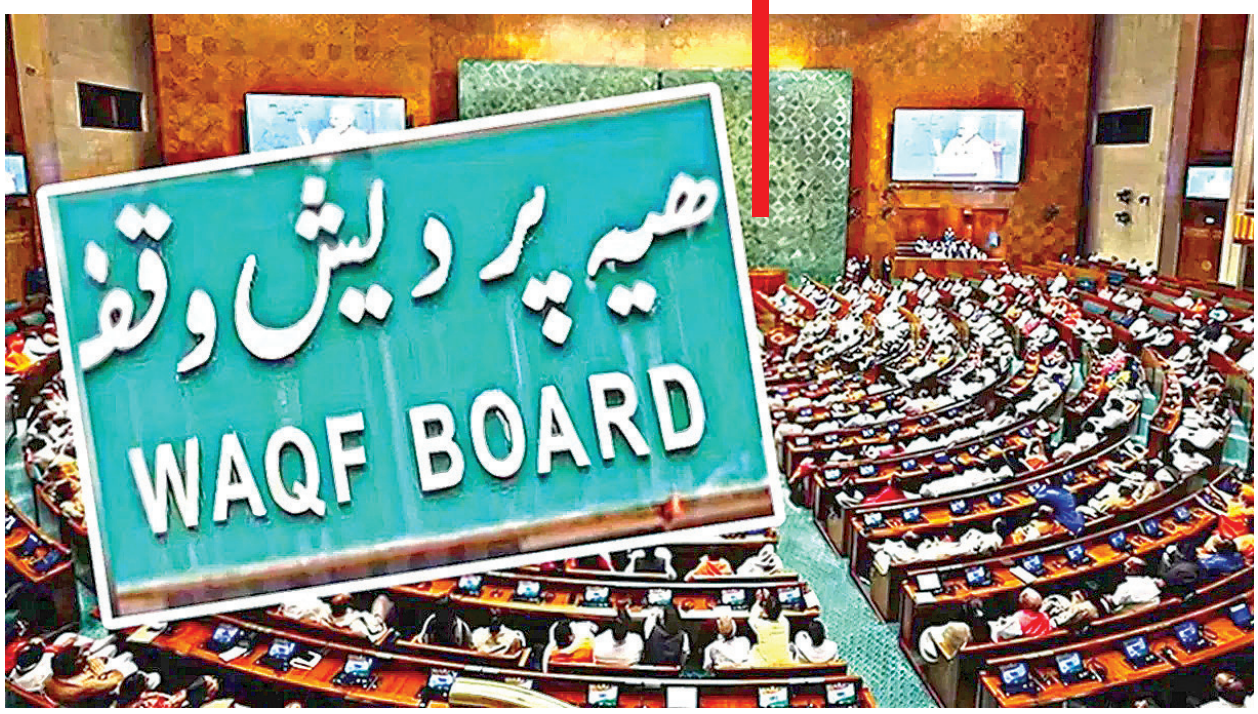

बिल में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार, और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन बताया गया है। विरोध के कारणों में मुस्लिम समुदाय और विपक्ष का मानना है कि यह धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है।

राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान पर विरोधों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 11 सदस्यीय बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार, बहुमत मुसलमानों का ही होगा।

पहले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की आपत्ति के कारण उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश किया गया और पारित हुआ। एक सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया कि यह कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा।

इस कानून का आगे क्या हश्र होगा और इसका राजनीतिक असर क्या होगा इसे देखना बाकी है। इस कानून की पहली अग्नि परीक्षा अभी बिहार चुनाव में हो सकती है जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू ,लोजपा मुस्लिमो की राजनीति करती रही है। इस बिल के संसद से पास होने के बाद ही जदयू टीडीपी,लोजपा और जयंत चौधरी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से अधिकतर मुस्लिम नेता बाहर हो गए हैं। बिहार में जदयू हमेशा मुस्लिम राजनीति के सहारे सत्ता तक पहुँचती रही है लेकिन अब मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ कितना सहयोग कर पाते हैं इसे देखना होगा।

शीर्ष अदालत के फैसले से सीएम ममता को मिली राहत

न्यूज़ डेस्क

कई परेशानियों से घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कोलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को ख़ारिज कर दिया जिसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के बंगाल कैबिनेट के फैसले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया गया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। वह ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती, जिसमें फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ हो।

देश के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और कहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया ''त्रुटिपूर्ण एवं दागदार'' थी।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वह ''अतिरिक्त पदों के सृजन के निर्णय पर सीबीआई जांच की दिशा के संबंध में'' पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी। ''अतिरिक्त पद'' से तात्पर्य ऐसे अस्थायी पद से है जो किसी ऐसे कर्मचारी को समायोजित करने के लिए बनाया जाता है जो नियमित पद पर नियुक्ति का हकदार है लेकिन वर्तमान में ऐसा नियमित पद उपलब्ध नहीं है। पीठ ने राज्य सरकार की याचिका के इस विशेष पहलू पर विचार करते हुए कहा, ''उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि मंत्रिमंडल के निर्णय पर अतिरिक्त पदों के सृजन के मुद्दे को सीबीआई को सौंपने का उच्च न्यायालय का निर्णय उचित नहीं था।'' पीठ ने मंत्रिमंडल के निर्णयों पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, ''हम स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में हमारी टिप्पणियां अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के निर्देश तक सीमित हैं और वे अन्य पहलुओं को लेकर सीबीआई की जांच एवं उसके द्वारा दायर आरोपपत्रों को किसी भी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करतीं।'' सुप्रीम कोर्ट के इस के फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। वह ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती, जिसमें फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ हो।

हज 2025 : सऊदी अरब ने भारत समेत कई देशों के वीजा पर लगाया अस्थायी बैन

न्यूज़ डेस्क

हज यात्रा नजदीक आ रही है और ऐसे में सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे तरकीब लगाकर हज करने का सपना देख रहे लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए सऊदी ने कुछ वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उमरा, बिजनेस और फैमली यात्रा के लिए जारी होने वाले वीजा पर यह बैन लगा है और यह मक्का की तीर्थयात्रा के समापन के साथ जून के मध्य तक प्रभावी रहेगा। इस प्रतिबंध से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्त्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को सहित 14 देश प्रभावित होंगे।

कथित तौर पर यह कदम व्यक्तियों को उचित रजिस्ट्रेशन के बिना हज करने की कोशिश करने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, उमरा वीजा रखने वाले व्यक्ति अभी भी 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के एआरवाई ने सऊदी अधिकारियों के हवाले से छापी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट जरूरी हो गया था क्योंकि कई विदेशी नागरिक इससे पहले उमरा या यात्रा वीजा लेकर सऊदी में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आधिकारिक अनुमति के बिना हज में भाग लेने के लिए अवैध रूप से वहीं रुक जाते हैं। इससे भीड़भाड़ अत्यधिक बढ़ जाती है और उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2024 में हज के दौरान ऐसी ही एक घटना में कम से कम 1,200 तीर्थयात्री मारे गए थे।

दरअसल सऊदी ने एक कोटा सिस्टम बना रखा है. तीर्थयात्रियों की संख्या को रेगुलेट करने के लिए हर देश के लिए एक खास हज स्लॉट दिया जाता है। यानी किसी एक देश से खास संख्या में ही लोग हज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हज में अवैध रूप से भाग लेने वाले लोग इस सिस्टम को दरकिनार कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वीजा बैन करने के इस कदम के पीछे एक दूसरा कारण सऊदी में जाकर अवैध रोजगार करना है। अधिकारियों ने कहा कि बिजनेस या फैमली वीजा का उपयोग करने वाले विदेशी, सऊदी अरब में अनधिकृत काम में लगे हुए हैं, वे वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और लेबर मार्केट में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस कदम का राजनयिक चिंताओं से कोई लेना-देना नहीं है और इसे केवल सुरक्षित और

बेहतर-व्यवस्थित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकारियों ने प्रभावित यात्रियों को नए नियमों का पालन करने के लिए कहा है. अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसे भविष्य में सऊदी में प्रवेश पर पांच साल के बैन का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि राजनयिक वीजा, रेजीडेंसी परमिट और विशेष रूप से हज के लिए वीजा लेने वाले लोग इस कदम से अप्रभावित रहेंगे।

वक्फ अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

न्यूज़ डेस्क

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे।

केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में 'कैविएट' दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया था। 'कैविएट' किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि उसकी सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। हाल ही में संसद से पारित होने के बाद बने इस वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न नेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद समेत विभिन्न पक्षों ने न्यायालय में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह संसद से पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया था।

फ्रांस से भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान

न्यूज़ डेस्क

भारत ने फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के जरिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है।खबर के मुताबिक 63,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की यह डील साइन हो सकती है। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल-सीट और 4 ट्विन-सीट राफेल मरीन विमान प्राप्त होंगे। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल-एम फाइटर जेट्स खरीदने को मंजूरी दी थी। इन जेट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर किया जाएगा।

इन 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डिलीवरी करीब चार साल में शुरू होने की उम्मीद है। पहला बैच 2029 के अंत तक नौसेना को मिल सकता है, जबकि 2031 तक सभी विमानों की तैनाती पूरी हो सकती है। इन विमानों को शामिल किए जाने के बाद इन्हें आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने मिग -29 के फ्लीट को अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा। इस समझौते से भारतीय वायु सेना की ताकत और बढ़ सकती है। नए राफेल मरीन फाइटर जेट्स इंडियन एयर फॉर्स के " बडी -बडी " एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम को भी मजबूती देंगे। इस सिस्टम में 10 तक राफेल विमान एक-दूसरे को हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी ऑपरेशन रेंज में तगड़ा इजाफा होगा।

राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभ्रांशु शुक्ल

न्यूज़ डेस्क

भारत जल्द ही अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने वाला है। भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभम शुक्ल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। बता दें कि मिशन एक्सिओम 4 की लॉन्चिंग डेट सामने आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे।

शुभम शुक्ल स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। यह मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाना है। इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो सभी अनुभवी भारतीय वायु सेना पायलट हैं, और जिन्हें इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु शुक्ल हैं।

10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे शुभ्रांशु शुक्ल एक कुशल लड़ाकू पायलट हैं, जिन्हें 2,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। शुक्ल ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे से स्नातक की, और बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। बाद में उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर से मास्टर

2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और एक टेस्ट पायलट बन गए। ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु के परिवार के अनुसार कारगिल के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की वीर गाथाओं को पढ़ने के बाद उन्हें सशस्त्र बल में शामिल होने की प्रेरणा मिली।

ऑफ़ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। वह 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और एक टेस्ट पायलट बन गए। ग्रुप कैप्टन शुभ्रांशु के परिवार के अनुसार कारगिल के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की वीर गाथाओं को पढ़ने के बाद उन्हें सशस्त्र बल में शामिल होने की प्रेरणा मिली। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी बड़ी बहन का कहना था कि 1999 में जब कारगिल में युद्ध छिड़ा था, तब वह सिर्फ 14 साल के थे। उस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय चौकियों पर अतिक्रमण कर लिया था। कठिन परिस्थितियों में सरवाईव करने की काबिलियत ने ही उन्हें मिशन गगनयान का हिस्सा बनाया।

मुंबई हमला का दोषी तहव्वुर राणा पहुंचा भारत

न्यूज़ डेस्क

आखिर में तहव्वुर राणा भारत के हाथ लग ही गया। वह कई सालों से अमेरिकी सरकार के गिरफ्त में थी और अब भारत सरकार ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। अमेरिका से लाये गए राणा को मुंबई के आर्थर जेल में रखा जाएगा। जेल को काफी चक चौबंद किया गया है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। पेशे से डॉक्टर रहा यह शख्स काफी खतरनाक है और इसने मुंबई हमले में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसे 26 /11 हमले का मास्टर माइंड माना जाता है। बता दें कि मुंबई के ताज होटल में 2008 में लश्करे तैयबा के आतंकियों ने भरी हमला किया था जिसमे 175 लोग मारे गए थे जबकि 300 से ज्यादाब लोग घायल हुए थे।

बता दें कि राणा कई साल से अमेरिका का कैदी रहा है। राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब तक वह लॉस एंजिल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था।

मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था।राणा ने ही हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की। यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था।हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया, जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था।उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रेकी की। बाद में यहीं पर हमले भी हुए।

अमेरिकी सरकार का कहना है, 'हेडली ने बताया है कि राणा ने एक शख्स को आदेश दिया कि वो हेडली के लिए मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड ऑफिस खोलने से जुड़ी फर्जी कहानी को सच दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए। राणा ने ही हेडली को सलाह दी कि भारत विजिट करने के लिए वीजा कैसे हासिल करना है। ये सारी बातें ईमेल और अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित हुई हैं।'

13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जो खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। डेविड हेडली मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। तहव्वुर राणा उसका बचपन का दोस्त था, जिसने इस हमले को अंजाम देने में उसकी मदद की थी।पिछले साल कोर्ट में सरकारी वकीलों ने तर्क दिया था कि तहव्वुर इस हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है। तहव्वुर को पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था।

राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि राणा इस पूरी साजिश का हिस्सा था और इस बात की पूरी आशंका है कि उसने आतंकी हमले को फंडिंग करने का अपराध किया है। 64 साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर हुसैन पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। इसके बाद वह 1997 में कनाडा चला गया और वहां इमिग्रेशन सर्विसेज देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम शुरू किया।

कनाडा से वह अमेरिका पहुंचा और शिकागो सहित कई लोकेशन पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोली। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया था। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है।

वक्फ बोर्ड : उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति, पंजाब में सबसे ज्यादा विवादित

न्यूज़ डेस्क

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पर्याप्त बहुमत के साथ संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किए जाने के के बाद अब यह कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने इस बिल पर मुहर भी लगा दी है और इसे गजट भी कर दिया गया है। यह कानून अब देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली कुल 8.8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 73,000 से अधिक विवादित हैं और विधेयक के तहत नए प्रावधानों से प्रभावित हो सकती हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन पंजाब में सबसे अधिक विवादित संपत्तियां हैं; केंद्र के डेटाबेस में वक्फ संपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा कब्रिस्तानों का है।6.2 लाख के साथ, सभी वक्फ संपत्तियों में से दो-तिहाई से अधिक कब्रिस्तान, कृषि भूमि, मस्जिद, दुकानें या घर हैं।

वक्फ एक निजी संपत्ति है जिसे मुसलमानों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य - धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए अलग रखा जाता है। जबकि संपत्ति के लाभार्थी अलग-अलग हो सकते हैं, संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर के पास माना जाता है।केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी वामसी डेटाबेस में सभी वक्फ संपत्तियों, उनके प्रकार, प्रबंधन और वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस डेटाबेस के अनुसार, 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं - 2.4 लाख के साथ, उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया बोर्डों में अब तक की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के बाद, पश्चिम बंगाल (80,480), पंजाब (75,511), तमिलनाडु (66,092) और कर्नाटक (65,242) में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के अलावा बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसमें अलग-अलग सुन्नी और शिया बोर्ड हैं; अन्य सभी राज्यों में एकीकृत वक्फ बोर्ड हैं।

डेटाबेस के अनुसार, अतिक्रमण, मुकदमेबाजी या अलगाव के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां वर्तमान में विवादों में हैं। मुकदमेबाजी के तहत संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं - व्यक्तियों से संबंधित दीवानी मुकदमों से संबंधित बाहरी मुकदमेबाजी, या वक्फ बोर्ड के भीतर विवादों से संबंधित आंतरिक मुकदमेबाजी। अलगाव वाली संपत्तियां वे हैं जो मालिकों द्वारा "अवैध" हस्तांतरण में शामिल हैं और दीवानी मुकदमों के अधीन हैं। अतिक्रमण वाली संपत्तियां वे हैं जिनके बारे में सरकार दावा कर सकती है कि वे उसकी भूमि पर बनी हैं और इस प्रकार ट्रिब्यूनल या प्रस्तावित विधेयक के तहत, जिला न्यायाधीश और संयुक्त सचिव रैंक के राज्य सरकार के अधिकारी वाले ट्रिब्यूनल द्वारा विवाद समाधान के लिए खुली हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो 1992 में ध्वस्त होने के बाद लंबे समय तक चलने वाले कानूनी मामले का विषय थी, भारत में सबसे प्रमुख वक्फ संपत्तियों में से एक थी। इस जगह पर विवाद, जहाँ अब राम मंदिर है, पहले स्थानीय अदालतों में सुना गया था, और फिर अंततः 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया

राज्यों में, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा विवादित संपत्तियाँ हैं। डेटाबेस के अनुसार, पंजाब की 75,511 वक्फ संपत्तियों में से 56.5% को "अतिक्रमित" माना जाता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हालाँकि, भारत में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन केवल 3,044 विवादित हैं। पश्चिम बंगाल की 3,742 विवादित वक्फ संपत्तियाँ पंजाब के बाद सबसे बड़ी संख्या बनाती हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर हैं।

कांग्रेस का गुजरात अधिवेशन प्रस्ताव बीजेपी -संघ का छद्म राष्ट्रवाद विभाजनकारी

राजनीतिक डेस्क

कांग्रेस ने दो दिवसीय गुजरात अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा कि उसका राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने वाला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का "छद्म राष्ट्रवाद" लोगों को विभाजित करना चाहता है।पार्टी ने यहां साबरमती नदी के तट पर आयोजित अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में राष्ट्रवाद और कई अन्य बिंदुओं को लेकर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। प्रस्ताव में कहा गया है, "राष्ट्रवाद के मायने देश की भू-भागीय अखंडता तो है ही, पर इस महान भूभाग में रहने वाले लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी है।" कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रवाद का अर्थ सभी देशवासियों के लिए समान न्याय की अवधारणा है, वंचितों-पीड़ितों-शोषितों के अधिकारों की रक्षा और उत्थान है, सद्भावना और भाईचारे की डोर में देश को बांधना है तथा भारत के बहुलतावादी और उदारवादी आचार, विचार और व्यवहार से है। कांग्रेस ने दावा किया, "कांग्रेस का राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने का है। बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को अनेकता को एकता में पिरोने का है। बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को खत्म करने का है।"

कांग्रेस ने यह भी कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद देश की साझी विरासत में निहित है और बीजेपी-आरएसएस का राष्ट्रवाद पूर्वाग्रह से ग्रसित है।उसने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, "जिन संगठनों ने ''स्वतंत्रता संग्राम'', विशेषतः ''भारत छोड़ो आंदोलन'' का विरोध किया, वही आज राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बाँटने का ठेका लिए हुए हैं।" कांग्रेस के प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी-आरएसएस का छद्म राष्ट्रवाद सिर्फ सत्ता का अवसरवाद है। उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीयता नहीं, सिर्फ सत्ताप्रियता है। वो सत्ता को हथियाने और बरकरार रखने के लिए देश को धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा, तथा खान-पान में बाँट रहे हैं। " मुख्य विपक्षी दल ने कहा, "त्याग, बलिदान, बहुलतावाद, और उदारवाद का कांग्रेस का रास्ता ही भारतीय राष्ट्रवाद है।"

गौरतलब है कि आठ तारीख को सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमिटी की चार घंटे तक बैठक चली और फिर 9 तारीख को साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस प्रतिनिधि पहुंचे थे। बता दें कि गुजरात में आयोजित कांग्रेस का यह 84 वां अधिवेशन था जो 9 अप्रैल को समाप्त हो गया। अधिवेशन में राहुल गांधी जमकर बोले। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान पर आक्रमण है। संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी-रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए।राहुल ने कहा बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहां गई 56 इंच की छाती।

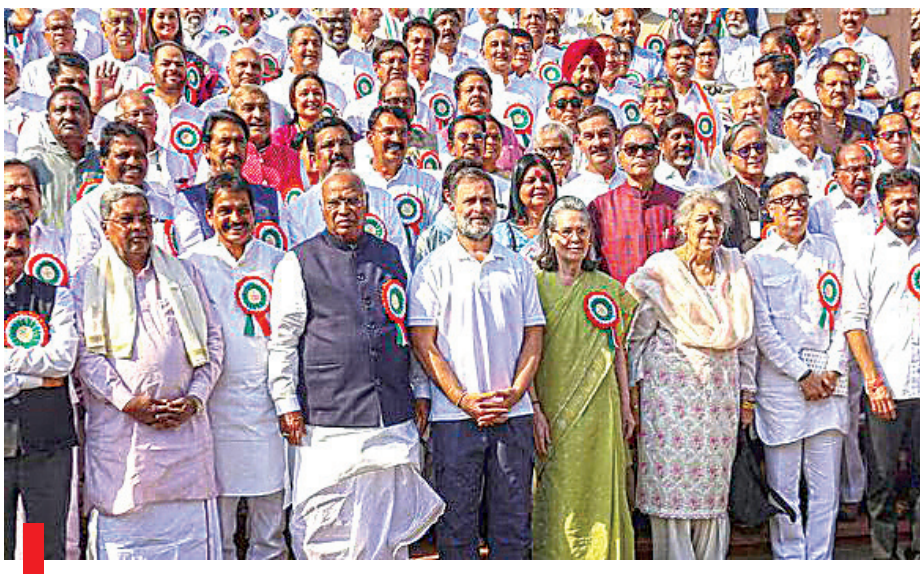

खड़गे ने बेरोजगारी के समय मोदी की चुप्पी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा दिखाती है कि भारत का विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि गांधीनगर भी कांग्रेस की देन है, जो उसके जमाने में बना। फिर भी मोदी कहते हैं कि यह उनके जमाने में हुआ। कांग्रेस ने बड़े-बड़े काम किए, पर भाजपा पूछती है कि 70 साल में क्या किया।

राहुल ने कहा- हमारी संगठन में काफी बैठकें हुई हैं। हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाएं, शक्ति बनाएं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है। ये आसान नहीं है। उनके पास धन हैं, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके पास सबकुछ है, लेकिन जीत हमारी होगी, हमारे साथ जनता का प्यार है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जनता उनके साथ क्या करने जा रही है। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में लिखते हैं कि क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी-रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी को देश में सम्मान मिले। हम चाहते हैं कि ये देश सबका हो। हम जाति, भाषा को यहां से फायदा मिले। राहुल ने कहा- हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। इनकी विचारधारा, फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। जिस दिन संविधान लिखा गया था, उस दिन आरएसएस ने रामलीला मैदान में संविधान को जलाया था। इसमें लिखा है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा होगा। सालों तक आरएसएस ने तिरंगे को सैल्यूट नहीं किया था। वे हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल कर देश का अडाणी-अंबानी को सारा धन देना चाहते हैं।

राहुल ने कहा- संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है। अडाणी-अंबानी को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश का पूरा धन दो-तीन लोगों के हाथ में होना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश के सभी वाइस चांसलर आरएसएस के होना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि देश में कोई खास भाषा ही पढ़ाई जाएगी। जिस पार्टी के पास विचारधारा, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी-आरएसएस के सामने खड़ी नहीं हो सकती। राहुल ने कहा कि आप बिहार के चुनाव में देखिएगा। महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, वहां बीजेपी ने चुनाव कैसे जीता। आने वाले समय में बदलाव आने वाला है। लोगों का मूड दिख रहा है। विचारधारा की लड़ाई है। हमारी गांधीजी की विचारधारा है। आरएसएस की विचारधारा में क्या फर्क है? संविधान हमारी विचारधारा है। इसमें बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, बासव की विचारधारा है। आज इस पर आक्रमण हो रहा है। राहुल ने कहा- पहले मोदी अमेरिका जाते थे। राष्ट्रपति से गले लगते थे। अब आपने ट्रंप से गले मिलने वाली फोटो देखी। ट्रम्प ने नए टैरिफ लगा दिए। मोदी जी की चूं तक नहीं निकली। जनता का ध्यान वहां न जाए, पार्लियामेंट में ड्रामा चलाया। सच ये है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोरोना में मोदी जी ने थाली बजवाई थी। अब कहां छिप गए हैं।

राहुल बोले- बीएचईएल, एचएएल, बीएसएनएल पहले दलित, पिछड़ा, अति-पिछड़ा लोगों को नौकरी देते थे, अब अडाणी-अंबानी जी को देख लीजिए, यहां आपको एक भी दलित, पिछड़ा, अति-पिछड़ा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़-बिहार-झारखंड में माइन चाहिए, कहीं का एयरपोर्ट चाहिए, ले लो। सारी अपॉर्च्युनिटीज 90% दलित, पिछड़ा, अति-पिछड़ा से छीनी जा रही है।बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहां के नेता से मिले। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कहां गई 56 इंच की छाती। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले- लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे। जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि जो तेलंगाना की हालत है, वह हर प्रदेश की है। तेलंगाना में 90% आबादी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी है। तेलंगाना में मालिकों की लिस्ट, सीईओ की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में इस 90% में से नहीं मिलेगा। राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने भाषण की शुरुआत शेर सुनाते हुए की- ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। उन्होंने आगे कहा- मैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत से आए कांग्रेस सदस्यों की ऊर्जा को सलाम करता हूं। यह कठिन समय है। सत्ता में बैठे लोगों ने नफरत को हथियार बना लिया है। कांग्रेस प्रेम की बात करती है। कांग्रेस न्याय के मार्ग की बात करती है। न्याय के लिए संघर्ष चल रहा है और न्याय के योद्धा का नाम राहुल गांधी है। गांधी और सरदार के गुजरात में खड़े होकर मैं सोचता हूं कि मैं कांग्रेस का एक आम आदमी हूं। जिसकी जड़ें महात्मा गांधी में मिलती हैं और उनके संस्कार राहुल गांधी में मिलते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं।

पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बेरोजगारी के समय मोदी की चुप्पी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा दिखाती है कि भारत का विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि गांधीनगर भी कांग्रेस की देन है, जो उसके जमाने में बना। फिर भी मोदी कहते हैं कि यह उनके जमाने में हुआ। कांग्रेस ने बड़े-बड़े काम किए, पर भाजपा पूछती है कि 70 साल में क्या किया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी ने वहां की गरीबी दूर नहीं की। खड़गे ने कहा कि हम भी हिंदू हैं, दलित और गरीब लोग भी इंसान और हिंदू हैं, लेकिन दर्शन के लिए जाएं तो गंगाजल डालकर पवित्र किया जाता है, जो शर्मनाक है। मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता और अपमान किया जाता है। उन्होंने पूछा कि दलित हिंदुओं की क्या दशा है, इसे मोदी सुधारें और शाह इस भेदभाव को बंद करें। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ ईडी और सीबीआई के पीछे दौड़ती है और छोटे व्यापारियों को परेशान करती है। सोनिया गांधी के आशीर्वाद से वे आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी गरीब व पिछड़े वर्ग के लिए ऊर्जा के साथ काम करते हैं। जिंदाबाद कहने से काम नहीं होगा, जीतकर आएंगे तब बात बनेगी। मोदी सरकार के मित्र अमीर हैं, जो गरीब के मित्र नहीं बनते। खड़गे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और राज्यपाल को बिल पास करने या वापस भेजने को कहा, जिसे उन्होंने सरकार और राज्यपाल के लिए थप्पड़ बताया। उनका कहना है कि मोदी विपक्ष को परेशान करने के लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं, और गलत काम करने पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। गांधीजी ने 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में सांप्रदायिक संस्थाओं के खिलाफ प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पूरे देश की सेवक है। सांप्रदायिक संस्था और उसके जहरीले सिद्धांतों और कार्यों के लिए उचित प्रतिक्रिया यह होगी कि कांग्रेस एक मजबूत जनमत तैयार करे। हमें विषैले सिद्धांतों का जवाब देने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा।

वक्फ बोर्ड के बाद कैथोलिक चर्च की बारी

न्यूज़ डेस्क

क्या वक्फ बोर्ड के बाद अब सरकार की नजर कैथोलिक चर्च पर टिकी है ? क्या कैथोलिक चर्च के खिलाफ भी कोई बड़ा निर्णय सरकार ले सकती है ? ये सवाल इसलिए किये जा रहे हैं कि बीते तीन अप्रैल को संघ द्वारा संचालित पत्रिका ऑर्गनाइजर में छापे एक लेख में कहा गया कि कैथोलिक चर्च ने भूमि स्वामित्व के मामले में वक्फ बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यह लेख छपने से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने इस बात की चर्चा की थी लेकिन संसद में वक्फ बिल पारित होने के बाद ही ऑर्गेनाइजर से इस लेख को हटा दिया गया।

3 अप्रैल को प्रकाशित लेख 'भारत में किसके पास अधिक जमीन है? कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस' में कहा गया है कि कैथोलिक चर्च के पास पूरे देश में करीब 17.29 करोड़ एकड़ जमीन है। बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास साढ़े आठ लाख एकड़ जमीन होने की बात की जा रही है। कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस' से जुड़े लेख में कहा गया है: "कई सालों से यह आम धारणा रही है कि वक्फ बोर्ड भारत में सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज़मीन मालिक है, हालांकि, यह दावा देश में ज़मीन के स्वामित्व के वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। भारत का कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा गैर-सरकारी ज़मीन मालिक होने का गौरव रखता है, जिसके पास देश भर में

फैले विशाल भूभाग हैं।"

लेख में कहा गया है कि "इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपये है, जो चर्च को भारत के रियल एस्टेट परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। 2012 तक, कैथोलिक चर्च के पास देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 2,457 अस्पताल डिस्पेंसरी, 240 मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज, 28 सामान्य कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3,765 माध्यमिक विद्यालय, 7,319 प्राथमिक विद्यालय और 3,187 नर्सरी स्कूल हैं। इसकी अधिकांश भूमि ब्रिटिश शासन के दौरान अधिग्रहित की गई थी। 1927 में, ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय चर्च अधिनियम पारित किया, जिससे चर्च को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की सुविधा मिली।'

ऑर्गनाइजर के लेख में एक प्रमुख विवाद की ओर भी इशारा किया गया, क्या कुछ भूमि संदिग्ध साधनों से प्राप्त की गई थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया: "कई रिपोर्ट बताती हैं कि चर्च द्वारा संचालित स्कूल और अस्पताल आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मुफ्त या कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करके लुभाते हैं, और बदले में, उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते हैं। लेख में आगे कहा गया है, "ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के भू स्वामियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया - या कुछ मामलों में उन्हें मजबूर किया गया - जिसके बाद उनकी जमीनों पर चर्च से जुड़े संगठनों ने कब्जा कर लिया। हालांकि चर्च इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन धर्मांतरण गतिविधियों से जुड़े अवैध भूमि अधिग्रहण के कई मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, जिससे भारत के सामाजिक-धार्मिक परिदृश्य में मिशनरी संस्थानों की भूमिका के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। कई मामले सामने आए हैं, जहां आदिवासी भूमि, जो कभी स्वदेशी समुदायों की थी, धीरे-धीरे विभिन्न बहानों के तहत चर्च अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई।"

बिहार की जातीय राजनीति को साध रही कांग्रेस

राजनीतिक डेस्क

कांग्रेस का बिहार में अपना कोई बड़ा आधार नहीं है और यही वजह है कि राहुल गाँधी बार -बार बिहार जाकर अपने लिए आधार वोट की तलाश कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस बिहार में मुख्यतौर पर अपने सहयोगी दलों और अपने नेताओं की व्यक्तिगत छवि के आधार पर जिंदा है। लेकिन पार्टी अब इस स्थिति को तोड़ना चाहती है। उसकी नजर दलित, अति पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों पर है। बिहार में दलितों को अपनी ओर करने के लिए कांग्रेस संविधान और आरक्षण को खतरे में बता रही है। इससे दलितों और उन जातियों को अपने पक्ष में लामबंद किया जा सकता है, जिसका वास्ता आरक्षण से है। संविधान के जरिए ही कांग्रेस मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ही कांग्रेस ने वक्फ बिल का संसद और संसद के बाहर जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस की इन कोशिशों का उन्हें फायदा होता हुआ भी नजर आया है। लोकसभा चुनाव में वह तीन अंक में सीटें लाने के करीब पहुंच गई है। दलित और मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रहा है। अभी इन दोनों वर्गों की राजनीति करने वाला कोई दल नहीं है।

इसके साथ ही बिहार में अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इनकी आबादी करीब 37 फीसदी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने पटना में होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में इतिहास से अति पिछड़ा वर्ग के उन नेताओं को सामने ला रही है, जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया या ठीक से जगह नहीं मिली। इसी तरह के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुद्धू नोनिया को 'संविधान सम्मान सम्मेलन' में याद किया जाएगा, जो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कांग्रेस की कोशिश आजादी की लड़ाई में इन वर्गों के नेताओं के योगदान को सामने लाना और उन्हें सम्मान देना है। कांग्रेस अति पिछड़ा वर्ग को यह भी बता रही है कि विकास की दौड़ में वे कितने पीछे छूट गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है। इसके जरिए कांग्रेस इन वर्गों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है।

बिहार में कांग्रेस की इन कोशिशों का नुकसान उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बिहार में राजद के वोट बैंक में मुसलमानों का स्थान बहुत अधिक है। वह बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और दलितों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। ऐसे में वोट बैंक की इस लड़ाई में दोनों सहयोगी दलों में मनमुटाव भी पैदा कर सकता है। कांग्रेस और राजद के रिश्ते को समझने के लिए पिछले साल लोकसभा चुनाव की एक घटना को देख सकते हैं। दरअसल बाहुबली नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। कांग्रेस उन्हें पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन राजद ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसकी वजह से पप्पू यादव को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। वो जीते भी.कांग्रेस को इससे फायदा होता है या नुकसान, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हुए दिख तो रही ही है।

ये बातें इसलिए कही जा रही है कि पिछले दिनों राहुल गांधी फिर से बिहार पहुंच गए। पहले बेगूसराय गए और कन्हैया कुमार द्वारा जारी पलायन रोको ,रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए और फिर पटना पहुंचकर संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए। बेगूसराय से लेकर पटना तक भीड़ देखने लायक थी। इस भीड़ में पुराने कोंग्रेसी तो शामिल थे ही ,बड़ी संख्या में महिलाएं ,नौजवान ,युवा महिलाये और युवा छात्रों का रेला लगा रहा। भीड़ को देखकर राहुल गाँधी गदगद हुए लेकिन बाकी पार्टियां निराश भी हुई। महागठबंधन की बड़ी पार्टी राजद भी भीड़ देखकर परेशान गति तो बीजेपी की परेशानी कुछ ही बढ़ती दिख रही थी। याद रहे बिहार में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं और इस चुनाव में कांग्रेस अपनी बड़ी भूमिका अदा करने की तैयारी में जुटी हुई है। राहुल का बार -बार बिहार दौरा यही बता रहा है कि वह बिहार की मौजूदा समस्या से खुद को कनेक्ट करने की तैयारी में हैं साथ ही बिहार के युवाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे आधार बनाकर युवाओं का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास भर है। लेकिन राहुल और कांग्रेस की नजर केवल युवाओं तक ही नहीं है। सच तो यही है कि जातीय राजनीति के लिए मशहूर बिहार में कांग्रेस को भी जातीय वोट की दरकार है।

एक समय था जब कांग्रेस के पास बिहार में बड़ा वोट बैंक था। सभी जातियों के वोट कांग्रेस के साथ जुड़े थे। समय बदला तो कई जातियां कांग्रेस से छिटक गई। फिर अधिकतर जातियों का वोट कांग्रेस को ही म इल्ते थे। जीव वोटों पर कांग्रेस की पकड़ थी उसमे शामिल थी ब्राह्मण ,भूमिहार ,दलित ,पिछड़े और मुसलमान जातियां। लम्बे समय तक कांग्रेस की किन जातियों पर पकड़ बनी रही। लेकिन 1990 के बाद बिहार में बड़ा बदलाव आया ,मंडल की राजनीति कुलांचे मारने लगी। कुछ नयी पार्टियों का उदय हुआ। जिन पार्टियों का उदय हुआ वे सब कांग्रेस विरोध के नाम पर ही सामने आयी। जातियों के नाम पर पार्टियों का गठन शुरू हुआ। बीजेपी भी ताकत बन कर उभरी। कई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस और बीजेपी बड़ी चुनाजुति बनी लेकिन सबसे ज्यादा सेंधमारी कांग्रेस में ही हुई। पार्टी में टूट होती गई। परतीय के नेता दूसरी जातिगत पार्टियों में जाने लगे। वोटों का बंटवारा शुरू हुआ। एक तरफ स्वर्ण जातियों को बीजेपी अपने पाले में ले जा रही थी तो दूसरी तरफ पिछड़े ,अति ;पिछड़े और मुसलमान को क्षेत्रीय पार्टियां अपनेर खेमे से जोड़ रही थी। करीब 20 वर्षों तक बिहार में जातियों की राजनीति कुलांचे मारती रही। कांग्रेस सिमटती गई। कांग्रेस कांग्रेस से लगभग सभी सवर्ण जातियां बाहर निकल गई। ब्राह्मण और भूमिहार जो बिहार में सबसे प्रभावशाली जातियां थी वह बीजेपी के साथ चली गई। राजपूत समाज भी कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के साथ जुड़ा गया। पिछड़ी जातियां कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जा जमी। बाकी जातियां अलग -अलग दलों में अपने स्वार्थ और निजी हित को देखते हुए कांग्रेस से निकल गई। मुसलमान समाज पर अधिकतर क्षेत्रीय दलों का ही प्रभाव रहा। अधिकतर मुस्लिम समाज राजद के साथ जुड़े। जो बचे वे कांग्रेस ,और बाकी पार्टियों के साथ आते -जाते रहे। जब कमंडल की राजनीति शुरू हुई तो मुस्लिम समाज बीजेपी को हराने वाली पार्टियों के साथ आती जाती रही। और अंत यही हुआ कि कांग्रेस के पास बिहार में किसी भी जाति का आधार वोट नहीं बचा।

आज बिहार में कांग्रेस का कोई आधार वोट नहीं है। किसी भी एक जाति पर उसकी ख़ास पकड़ नहीं है। किसी भी मुस्लिम समाज पर कांग्रेस की पकड़ नहीं रही। फिर कांग्रेस के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने वे भी कांग्रेस को धोखा देते रहे। पार्टियां बदलते रहे और कांग्रेस के वोट बैंक को भी बेचते रहे। कांग्रेस वोट विहीन होती चली गई। बस बिहार में कांग्रेस जिंदा भर रहा। हर चुनाव में कुछ सीटें उसे मिलती रही जो बाद में पाला बदलकर दूसरी पार्टियों की मजबूती में कारगर होती रही। जाहिर है कांग्रेस की इस बर्बादी में सबसे ज्यादा दोषी तो कांग्रेस नेता ही रहे लेकिन बाद में प्रदेश की सभी क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को कमजोर करने में कोई कोताही बरतने में कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन अब कांग्रेस खुद के पैर पर खड़ा होने को तैयार है। उसे संगठन भी मजबूत करना है। उसे प्रदेश में कोंग्रेसी नेता भी खड़ा करना है और उसे जातीय वोट भी चाहिए। युवाओं की शक्ति चाहिए। महिलाओं की ताकत चाहिए और किसान ,मजदूरों का साथ भी चाहिए। कांग्रेस को बेरोजगार लोगों का झुंड भी चाहिए और प्रदेश से पलायन कर दुस्तरे प्रदेश में बेइज्जत होने वाले बिहारी समाज का साथ भी चाहिए। यही वजह है कि इस साल भार राहुल के अजेंडे में सिर्फ बिहार ही है।

कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं कि बिहार में हम कितना ताकतवर होंगे अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तय मानिये बिहार के चुनावी परिणाम को हम इस बार बदलने की तैयारी में है। हम बिहार को उस स्थिति में लाने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम भले ही बिहार में अकेले सरकार नहीं बनाये लेकिन हम मिलकर सरकार बनाएंगे और यही समझ के साथ कांग्रेस बिहार में बहुत कुछ करती दिख रही है।

जाहिर है कांग्रेस के लोग बिहार को लेकर कुछ अलग रणनीति भी बना रहे हैं। गुजरात में हो रहे कांग्रेस अधिवेश के बाद बिहार के लिए कई और रणनीति सामने आ सकती है। राहुल गाँधी के साथ ही प्रियंका गाँधी और पार्टी के कई बड़े नेताओं को बिहार में उतारने की तैयारी चल रही है। पप्पू यादव को कोई बड़ी भूमिका देने की बात की जा रही है। सीमांचल की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव को दी जा सकती है और ऐसा हुआ तो जाहिर है कि कांग्रेस बिहार चुनाव में कुछ अलग कर सकती है। अभी बिहार में राहुल गाँधी की नजर खासकर दलित ,अति पिछड़े और मुस्लिम वोट पर है। इन तीनो जातियों के वोट बैंक को एक साथ कर दिया जाए तो लगभग 50 फीसदी से ज्यादा वोट बैंक बन जाते हैं। इन वोट बैंक में से कुछ जातियों के वोट को भी कांग्रेस के साथ जोर दिया गया तो बिहार की राजनीति पलटी मार सकती है। जिस तरह क्सासे भूमिहार समाज से आने वाले कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है उसका लाभ कांग्रेस को मिलता भी दिख रहा है। इसी तरह से रविदास समुदाय से आने वाले राजेश कुमार राम को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर करीब पांच फीसदी रविदास वोट पर कांग्रेस की नजर लग गई है। और अतिपछड़ो की आबादी बिहार में 37 फीसदी से ज्यादा है। अगर इसमें से कुछ जातियां भी कांग्रेस के साथ जुड़ती है तो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

आखिर झामुमो अपने संविधान में संशोधन क्यों कर रही है?

राजनीतिक डेस्क

झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संविधान में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए पार्टी ने संविधान संशोधन कमेटी का भी गठन कर दिया है। पार्टी का 13 वां दो दिवसीय अधिवेशन 13 और 14 अप्रैल को होने जा रहा है और इसकी तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक़ पंचायत से जिला कमेटी की सांगठनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन को प्रस्ताव सदस्यों द्वारा लाये गये हैं। कमेटी पार्टी के संविधान में करीब एक दर्जन संशोधन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। पंचायत और जिला कमेटी के अधिकार को लेकर संविधान संशोधन कमेटी ने मंथन किया है। इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारी को सशक्त बनाने पर विचार हो रहा है। पार्टी महासचिव ने कहा कि पूरे झारखंड में झामुमो बड़ी राजनीतिक ताकत बना है। हमें जनता का लगातार प्यार मिल रहा है। पार्टी पर आदिवासी-मूलवासी का विश्वास बढ़ा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मार्ग दर्शन और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारा विस्तार हो रहा है। ऐसे में एक-एक कार्यकर्ता की जवाबदेही बढ़ी है। हमारी कोशिश है कि पार्टी के पदाधिकारी व नेता जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी बने। पार्टी के विधायक और सांसद भी सांगठनिक काम में अपनी भूमिका को और तेज करेंगे। इन सारी चीजों को संविधान संशोधन के माध्यम से समाहित किया जायेगा।

पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि कमेटी संविधान संशोधन को लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में लगी है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव महाधिवेशन में पेश किया जायेगा। संविधान संशोधन के एक-एक बिंदुओं पर चर्चा होगी। महाधिवेशन में पारित होने के बाद ही यह पार्टी के अंदर कानून माना जायेगा। हमारी कोशिश है कि संगठन को सशक्त करने की दिशा में काम हो। बदली परिस्थिति में पार्टी को व्यापक बनाने के लिए संविधान में बदलाव जरूरी है।

बिहार में नयी पार्टी 'हिन्द सेना' की त्रिपुण्ड निशान के साथ इंट्री

राजनीतिक डेस्क

बिहार चुनाव में इस बार कई तरह के खेल होने की सम्भावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की पानी तैयारी है और वह बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर हालांकि अभी हाल में पटना में हुए छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था और इसका लाभ कांग्रेस की छत्र इकाई एनएसयूआई को हुआ भी। दो सीटों पर कांग्रेस की छात्र इकाई की जीत हुई। लेकिन अब विधान सभा चुनाव में जन सुराज का क्या स्टैंड होगा यह देखने की बात होगी। यह भी बता दें कि राहुल गांधी और गांधी परिवार से आज भी बेहतर स्टैंडिंग है लेकिन चुनाव में वे कांग्रेस के साथ जायेंगे या अकेला मैदान में उतरेंगे यह आज भी पहेली है। लेकिन बिहार की राजनीति को हांकने के लिए इस बार एक और नयी पार्टी का अवतरण हो गया है। इस पार्टी का नाम है हिन्द सेना और पार्टी का निशान है त्रिपुण्ड। बीते दिनों पटना परेटी की घोषणा की गई। बड़ी संख्या में लोग प्रेस वार्ता में पहुंचे थे। जेकात्रे भी लगे और बिहार को बदलने का ऐलान भी हुआ।

बड़ी बात तो यह है कि इस पार्टी की स्थापना एक पूर्व आपीएस अधिकारी ने की है। उनका नाम है शिवदीप लांडे। बड़े ही काबिल अधिकारी रहे हैं लांडे और जब वे अपनी सेवा बिहार सरकार को दे रहे थे तब बिहार की जनता में उनकी काफी इज्जत थी। लोग उन्हें आँखों पर रखते थे। अपराध जगत लोग उनके नाम से कांपते थे। जहाँ जाते थे अपराधी भाग खड़े होते थे। लेकिन अब लांडे राजनीति करेंगे। किस जाति और जमात की राजनीति वे करेंगे इसका कोई विचार अभी नहीं है। उनकी समझ यही है कि वे बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और युवाओं के साथ मैदान में उतरेंगे। बिहार की परेशानी ख़त्म करेंगे और पेपर लिक की सभी समस्याओं को सदा के लिए ख़त्म कर देंगे। प्रेस वार्ता में जब वे बोल रहे थे लोग खूब तालियाँ बजा रहे थे। याद रहे लांडे नीतीश कुमार के काफी प्यारे अधिकारी रहे हैं।

शिवदीप लांडे ने बताया कि उन्होंने क्यों राजनीति के मैदान में पैर रखा और उनका उद्देश्य क्या है। शिवदीप लांडे ने सियासी पार्टी का ऐलान करते ही पुलिसिया अंदाज में चेतावनी भी दी है। शिवदीप लांडे ने कहा कि युवाओं की दशा और दिशा बदलने के लिए राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाया है। युवाओं के लिए ही वो राजनीति में आए और युवाओं के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पेपर लीक करने वालों को चेतावनी भी दी। लांडे ने कहा- 'अगर हमारी पार्टी आई तो फिर कोई पेपर लीक करके दिखा दे। सब ठीक कर दिया जाएगा। 360 डिग्री कार्रवाई होगी। ' हालांकि बीपीएसएसी अभ्यर्थियों से मिलने के सवाल पर उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे ने अपनी राजनीति पार्टी का ऐलान कर दिया है। पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद तरह-तरह के कयास उन्हें लेकर लगाए जा रहे थे। पटना में प्रेस कांफ्रेंस करके शिवदीप लांडे ने अपनी सियासी पार्टी के बारे में बताया। हिंद सेना नाम से उनकी पार्टी बिहार चुनाव के मैदान में उतरेगी। पार्टी के सिंबल का आकार 'त्रिपुंड' जैसा है। अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि 'हिंद सेना' नाम रखने की भी बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि हिंद पहले भी सर्वोपरि था, अभी भी है और आगे भी रहेगा।

शिवदीप लांडे ने कहा कि जब वो पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर लोगों से मिलने के लिए जिलों में गए तब भी उनका मकसद जय हिंद ही था। उन्होंने कहा कि हिंद उनके खून के हर कतरे में मिला हुआ है।लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी 'हिंद सेना' में सेना शब्द उन लोगों के लिए है जो इस पार्टी से जुड़ेंगे और बिहार के हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी से जुड़ने वालों को लड़ाकू बताया। हिंद सेना' पार्टी के सिंबल के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का सिंबल त्रिपुंड है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे मस्तक पर त्रिपुंड जैसा आकार बनता है। त्रिपुंड को अपनी पार्टी का विचारधारा बताते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि इसका उद्देश्य मानवता, न्याय और सेवा है। उन्होंने कहा कि जब वो जिलों का दौरा कर रहे थे तो मानवता की कमी लोगों में दिखी। लांडे की राजनीति बिहार में क्या करतव दिखाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन लांडे की राजनीति में प्रवेश से कई दलों में निराशा के बादल छा गए हैं। कई पार्टियां यह मान रही है कि इस बार के चुनाव में काफी संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह देखना होगा

दमोह में फर्जी डॉक्टर ने किया हार्ट का ऑपरेशन, 7 की मौत

न्यूज़ डेस्क

मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर ने मिशन अस्पताल में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए, जिसमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद फर्जी डॉक्टर फरार हो गया जिसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुक़दमे लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस तरह के फर्जी डॉक्टरों की जांच क्यों नहीं की जाती ?रिपोर्टों के अनुसार, भारत में कई फर्जी डॉक्टर बगैर किसी योग्यता के मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है कि देश में कितने फर्जी डॉक्टर हैं।

खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एनजोन केम के नाम पर फर्जी डॉक्टर ने ढाई महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर दिए। बताया जा रहा है कि इनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मामला सामने आते ही फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। मेडिकल फर्जीवाड़े का यह कोई पहला मामला नहीं है। 2023 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक घटना देखने को मिली थी, जहां झोलाछाप डॉक्टर की गलत प्रैक्टिस की वजह से 33 लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए।

भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टरों की सही संख्या बता पाना मुश्किल है। सरकार के पास भी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावा किया जा चुका है कि देश में बिना क्वालिफिकेशन मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की संख्या हजारों में है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत में लगभग 2-3 लाख फर्जी डॉक्टर हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत के आधे से अधिक डॉक्टर फर्जी हैं। 2018 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में इलाज के दौरान लगभग 20 फीसदी मौतें फर्जी डॉक्टरों की वजह से होती हैं। दावा किया गया था कि 2001 में एलोपैथिक डॉक्टर होने का दावा करने वालों में से 31 प्रतिशत केवल मिडिल क्लास तक पढ़े थे और 57 फीसदी के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी। स्टडी में यह भी बताया गया था कि ग्रामीण भारत में केवल 18.8 प्रतिशत एलोपैथिक डॉक्टरों के पास ही मेडिकल डिग्री थी।

हालांकि सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे को भारत ने खारिज कर दिया था। 2018 में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया था कि रिपोर्ट गलत है क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसलिए सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के पास मेडिकल प्रैक्टिस करने की योग्यता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15 स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नामांकित डॉक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को राज्य में मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हेल्थ राज्य का विषय है, इसलिए झोलाछाप डॉक्टरों के मामलों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से झोलाछाप

डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

कानून को सख्ती से लागू न किए जाने की वजह से देश में झोलाछाप डॉक्टरों की समस्या बनी हुई है। भारत सरकार और विभिन्न मेडिकल एजेंसियां इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सवाल है ये फर्जी डॉक्टर कौन हैं, और ये कहां से आते हैं?असल में, झोलाछाप डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने वाले ज्यादातर लोग किसी डॉक्टर के यहां मददगार या कंपाउंडर के तौर पर काम करते हैं। कुछ साल काम करने के बाद ऐसे लोग खुद ही मेडिकल प्रैक्टिस करने लगते हैं। भारत में इन्हें 'झोला छाप'या क्वैक डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन असल में ये लोग मेडिकल सर्विस के एक बड़े गैप को भरते हैं।

ये क्वैक डॉक्टर खासकर गांवों में एक्टिव हैं, जहां असली डॉक्टरों की कमी है या उनकी फीस इतनी अधिक है कि गरीब उनके पास पहुंच नहीं सकते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत में कम से कम 10 लाख झोला छाप डॉक्टर हैं। इनमें से लगभग 4 लाख वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। हालांकि इन आयुष डॉक्टरों में से सभी फर्जी नहीं होते, उन्हें एलोपैथी दवाइयां लिखने का अधिकार नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी एक गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत को प्रति 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि भारत में लगभग 1500 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। यह कमी आश्चर्यजनक है, जबकि भारत के पास दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन सरकार का कहना कि 836 की आबादी पर देश में एक डॉक्टर उपलब्ध है। 2 अगस्त 2024 को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी थी। समस्या यह भी है कि हर साल मेडिकल कॉलेजों से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों की संख्या सीमित है, जो सामान्यतः प्रत्येक कॉलेज से 100 से 150 छात्रों के बीच होती है। मसलन एम्स दिल्ली हर साल अपने ग्रेजुएट कोर्स में केवल 72 छात्रों का दाखिला लेता है जबकि यहां लगभग 80,000 से 90,000 एप्लिकेशन आते हैं।

वक्फ कानून के बाद कब्रिस्तानों पर बने सरकारी दफ्तरों पर चलेंगे बुलडोजर

न्यूज़ डेस्क

संसद से वक्फ बिल पास होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भोपाल में अफरातफरी का माहौल है। अब इस बात की सम्भावना बढ़ गई है कि नए वक्फ बिल के बाद राजधानी में जल्द ही वक्फ की जमीनों पर कब्जे हटाने शुरू होगें। वक्फ रेकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा कब्जे कब्रिस्तानों पर हैं। करीब 100 कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं। इनमें कहीं बस्तियां हैं तो कहीं काम्पलेक्स तो सरकारी दफ्तर भी काबिज हैं।

बोर्ड के रेकॉर्ड में राजधानी भोपाल में 7700 वक्फ सम्पत्तियां हैं इसमें 135 कब्रिस्तान हैं। लेकिन इनमें से 30 ही बचे हैं। कब्रिस्तानों के संरक्षण के लिए काम कर रहे जमीयत के सचिव इमरान हारून के मुताबिक वर्तमान में भोपाल टॉकीज चौराहा, पुराना आरटीओ ऑफिस, नरेला संकरी, कोलार, जहांगीराबाद सहित कई इलाकों में कब्रिस्तानों के नामोनिशान भी नहीं बचा। पीएचक्यू के पास सरकारी दफ्तर के पीछे कब्रों के निशान अब भी हैं।

वक्फ बोर्ड ने जिला प्रशासन को 7700 संपत्तियों की जानकारी दी है। राजस्व रेकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। इसके आधार पर बोर्ड का रिकॉर्ड भी अपडेट होगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल के मुताबिक प्रशासन को सभी की जानकारी दी चुकी है।इमरान हारून ने बताया कि शहर में करीब 70 प्रतिशत कब्रिस्तान खत्म हो गए हैं। कब्रिस्तान पर बस्तियां बस गई हैं तो कहीं लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। नए बिल से निजी कब्जों पर तो कार्रवाई संभव है सरकारी के लिए क्या होगा कुछ पता नहीं। उसके बदले बोर्ड क्या सरकार से जमीन लेगी।

मुस्लिम महासभा के मुनव्वर अली ने बताया कि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। बीते साल ही शहर के कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए जगह की कमी की बात सामने आई। निजी कब्जाधारियों पर तो कार्रवाई हुई लेकिन जिन जमीनों पर सरकार का कब्जा है उनके बदले क्या होगा। कब्रिस्तान के बदले जमीन मिलनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में फिर 31 नक्सलियों ने किया सरेंडर

न्यूज़ डेस्क

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सरेंडर जारी है। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि या तो वे मुख्यधारा में लौट आये नहीं तो मारे जायेंगे। पिछले साल भर से जीडस अंदाज में नक्सलियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई चल रही है उससे नक्सलियों में भी भय पैदा हो गया है। कारण यह है कि अब बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। पहले नक्सली और सुरक्षाकर्मी के बीच जब आमना -सामना होता था तो नक्सली जंगलों की आर में भारी पड़ जाते थे और उसका लाभ उठकर सुरक्षामार्मियों को मार गिराते थे ,लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब नक्सली पर भारी सुरक्षाकर्मी हो गए हैं। यही वजह है कि अब नक्सली लगातार सरेंडर करने को बाध्य हो रहे हैं। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4.5 लाख के तीन ईनामी सहित कुल 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं, नारायणपुर में 5 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यानी कुल 31 नक्सलियों ने हाथ खड़े किए हैं। ये समर्पित नक्सली सड़क खोदना, नक्सली बैनर पोस्टर लगाने जैसी घटनाओं में शामिल थे। ये सभी लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर हुआ है। दंतेवाड़ा में इस अभियान के तहत अबतक 224 ईनामी सहित 953 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में लगातार अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं अब नक्सलियों में खाकी का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है।

नारायणपुर जिले के माड़ डिवीजन अंतर्गत कुतुल, नेलनार और परलकोट एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय रही 5 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी महिला नक्सलियों पर शासन द्वारा एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हुए मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। पुलिस और प्रशासन के सामने समर्पण करने वाली इन महिलाओं ने बताया कि वे अब हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहती हैं। लंबे समय तक जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहने और माओवादी संगठन की विचारधारा से मोहभंग होने के कारण उन्होंने यह फैसला लिया है। प्रशासन ने इस आत्मसमर्पण को एक सकारात्मक संकेत बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे अन्य माओवादी भी प्रेरित होकर आत्मसमर्पण की राह अपनाएंगे।

एनआईए के निशाने पर खालिस्तानी आतंकी गोल्डी बराड़

छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बम विस्फोट की घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए एजेंसी जांच में जुटी हुई है। हमलों के तुरंत बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जिम्मेदारी ली थी।

न्यूज़ डेस्क

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के निशाने पर खालिस्तानी आतंकी गोल्डी बराड़ आ गया है। एनआईए की टीम ने बीते मंगलवार को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के कई ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए की टीम ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने कनाडा स्थित आतंकवादी बराड़, अमेरिका स्थित गैंगस्टर रणदीप मलिक से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने गुरुग्राम के सेक्टर-29 में बने वेयरहाउस क्लब और ह्यूमन क्लब पर हुए ग्रेनेड हमले की जांच के सिलसिले में पहुंची है।

जांच एजेंसी ने बताया कि आज सुबह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न जिलों में आठ स्थानों पर छापेमारी की गई है। जहां छापेमारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बम विस्फोट की घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए एजेंसी जांच में जुटी हुई है। हमलों के तुरंत बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जिम्मेदारी ली थी। वहीं एनआईए की जांच में मलिक और नामित आतंकवादी बराड़ का पर्दाफाश हुआ। जो पहले क्लब मालिकों को धमकी दिया करता था और उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करता था।

गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 21 दिनों की फरलो

न्यूज़ डेस्क

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को यह राहत दी गई है। फरलो मिलने के बाद 9 अप्रैल के सुबह-सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम सिरसा डेरा पहुंच गया है। राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची थी। इस बार वह सिरसा डेरा में रहेगा। राम रहीम को यह राहत डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस से पहले मिली है। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, जिसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने की संभावना है। इससे पहले राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। इस तरह पिछले चार सालों में कुल 13वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। अगस्त 2017 में दो शिष्याओं से रेप के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाये जाने के बाद 28 जनवरी को उसे 30 दिनों की पैरोल दी गई थी।

इस दौरान पहली बार वह सिरसा में अपने डेरे में 10 दिनों तक रुका था. बाद में वह उत्तर प्रदेश के बागपत में रहा था। राम रहीम को इससे पहले 20 दिन की पैरोल दी गई थी। यह पैरोल पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से चार दिन पहले दी गई थी।

पिछली बार उसने अपने पिता मगहर सिंह की पुण्यतिथि 5 अक्टूबर का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी, जिसे परमार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल अक्टूबर से पहले हरियाणा सरकार ने राम रहीम को अगस्त में 21 दिन की फरलो दी थी, जो 2 सितंबर को समाप्त हो गई थी। राम रहीम फिलहाल राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने राम रहीम की अपनी दत्तक बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल की याचिका खारिज कर दी थी। राम रहीम को दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2019 में उन्हें और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त 2017 को दोषी करार होने के बाद पंचकूला और सिरसा में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे।

6500 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान ने दिया वीजा

न्यूज़ डेस्क

इस बार 6500 से ज्यादा सिख श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे और गुरुद्वारा पंजा साहिब ,गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने इस वैशाखी के लिए 6500 से ज्यादा भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए वीजा जारी कर दिया है। बीते 50 साल में यह पहली बार है, जब पाकिस्तान सरकार ने बैसाखी के लिए भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को एडिशनल वीजा दिए हैं। बैसाखी का मुख्य कार्यक्रम 14 अप्रैल को ननकाना साहिब में होगा। ननकाना साहिब सिखों के लिए बेहद खास और पवित्र धार्मिक स्थल है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनियाभर के सिख श्रद्धालु इस मौके पर लाहौर पहुचेंगे। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालुओं को वीजा के जारी होने के बाद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पाकिस्तान हाई कमीशन ने बैसाखी के लिए बीते साल 2,250 वीजा जारी किए थे। आमतौर पर वीजा की संख्या 2,500 से 3,000 के बीच रहती थी लेकिन इस साल पीएचसी ने रेकॉर्ड 6,500 वीजा जारी किए हैं। हाई कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार के इतनी बड़ी संख्या में वीजा जारी करने का मकसद दोनों ओर की संस्कृतियों और धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया है कि बैसाखी मेला 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 20,000 स्थानीय श्रद्धालु और 7,000 भारतीयों के अलावा दूसरे देशों के श्रद्धालु शामिल होंगे। इस दौरान 16 अप्रैल को करतारपुर में धार्मिक कार्यक्रम होंगे और कबड्डी मैच खेला जाएगा।

जल संकट पर केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार से मांगी रिपोर्ट

न्यूज़ डेस्क

राज केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ''राजस्थान झालावाड़ में जल संकट को लेकर पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे द्वारा उठाई गई चिंता को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। राजस्थान सरकार से इस संबंध में तात्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।'' दरअसल ,राजस्थान में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। पिछले दिनों झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे के दौरे पर पहुंचीं वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी।

वसुंधरा राजे के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राजस्थान सरकार से जवाब तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है वसुन्धरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देर रात दो पोस्ट करते हुए झालावाड़ जिले में जल जीवन मिशन में कामकाज को लेकर अफसरों पर सवाल उठाए। वसुंधरा राजे ने एक्स पर लिखा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती? सिर्फ़ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है। अफ़सर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफ़सर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।उन्होंने रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए।

पूर्व सीएम राजे ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने 42 हज़ार करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं। पाई-पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया? पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर रहे। इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल है। यह तो अप्रेल का हाल है। जून-जुलाई में क्या होगा?

न्यू देहली पोस्ट

ओडिशा में पांडियन को लेकर बीजद में टूट की सम्भावना बढ़ी

राजनीतिक डेस्क

वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करने के लिए जहाँ देश की कई पार्टियां मुश्किलों का सामना कर रही है वही ओडिशा की नवीन पटनायक की पार्टी बीजद टूट के कगार पर पहुँच गई है। पार्टी के कई सांसदों ने वक्फ बिल का समर्थन किया था जबकि नवीन पटनायक ने ऐसा नहीं करने की बात कही थी और उन्होंने यही कहा था कि पार्टी को वक्फ संशोधन बिल का खिलाफ करना है ताकि मुसलमानों के बीच पार्टी की छवि ख़राब नहीं हो। लेकिन नवीन पटनायक के इस आदेश के बाद भी पार्टी के कई नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग की। यह बात और है कि वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया और फिर यह कानून भी बनकर देश में लागू भी हो गया। लेकिन इस बिल को लेकर अब बीजद के भीतर टूट की सम्भावना बढ़ गई है। नवीन पटनायक के खिलाफ जाने वाले नेताओं का कहना है कि जो भी हुआ उसके लिए बीके पांडियन जिम्मेदार हैं। बता दें कि बीके पांडियन पूर्व नौकरशाह हैं अजर नवीन पटनायक के ख़ास माने जाते हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक पर रुख बदलने को लेकर बीजद में संकट गहराने के बीच पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपने विश्वस्त सहयोगी वीके पांडियन का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व नौकरशाह को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 महीने से अधिक समय पहले पार्टी छोड़ दी थी और वह पार्टी के किसी भी काम में शामिल नहीं हैं। नवीन ने कहा , "मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पांडियन ने अतीत में न केवल राज्य बल्कि पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए, उन्हें किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने 10 महीने से अधिक समय पहले पार्टी छोड़

दी थी और वह पार्टी के किसी भी काम में शामिल नहीं हैं।" इससे पहले पार्टी के कई नेताओं ने शहर के पटिया इलाके में एक होटल में बैठक कर मौजूदा हालात पर चर्चा की थी । बैठक में पूर्व मंत्री देबी मिश्रा, अरुण साहू, शशि भूषण बेहरा, अशोक पांडा, संजय दास बर्मा, भूपिंदर सिंह और अंशुमान मोहंती शामिल थे। हालांकि, नवीन ने पार्टी के सदस्यों द्वारा होटलों में की जाने वाली बैठकों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "उनके पास पार्टी कार्यालय 'शांख भवन' है, जो एक बड़ी इमारत जहाँ उन्हें अपनी बैठकें करनी चाहिए।"

पार्टी अध्यक्ष ने पांडियन को निशाना बनाने के लिए पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक और वरिष्ठ नेता प्रवत त्रिपाठी पर भी निशाना साधा। त्रिपाठी ने कहा था कि पूर्व नौकरशाह बीजद के पतन और 2024 के चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। नवीन ने त्रिपाठी के लिए कहा, "मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक प्रवत त्रिपाठी को कुछ साल पहले बीजद से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन पर चिट-फंड मामले में आरोप लगाया गया था और उन्होंने कुछ साल जेल में बिताए हैं।" उन्होंने कहा कि त्रिपाठी पार्टी से संबंधित नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष ने 11 नवंबर, 2017 को बीजद से त्रिपाठी का निलंबन रद्द कर दिया था, जो उस समय बांकी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अक्टूबर 2014 में चिट फंड घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद त्रिपाठी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, उनके बेटे देवी रंजन त्रिपाठी को पार्टी ने नामित किया और वे विधायक बने। उस दिन, पार्टी के सात युवा नेताओं ने नवीन को पत्र लिखकर उनसे भविष्य की कार्रवाई की घोषणा करने का आग्रह किया।

उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान के मुद्दे पर संसदीय दल के बंटे रहने के तरीके पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "इससे पूरे राज्य के बीजू जनता दल के लोग आहत हुए हैं। इस मावह ईडी मले में पार्टी की नीति के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।" मोहंती, देवी रंजन त्रिपाठी, पूर्व विधायक रुद्र प्रताप महारथी, चंद्र सारथी बेहरा, बिष्णुब्रत राउत्रे और प्रणब बालाबंतराय सहित युवा नेताओं ने भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को शहर के एक होटल में मुलाकात की थी।

तमिलनाडु के राज्यपाल की करवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

न्यूज़ डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और राज्य सरकार के बीच विधेयकों को मंजूरी देने के विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह मामला राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबित रखने और राष्ट्रपति को भेजने से जुड़ा था। कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने की कार्रवाई को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया। और कोर्ट ने राज्यपालों के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए विधेयकों पर समयबद्ध फैसले का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और राज्य सरकार के बीच विधेयकों को मंजूरी देने के विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा से पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से फैसला लेना होगा। यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न देने और राष्ट्रपति के पास भेजने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विधानसभा दोबारा विचार के बाद विधेयक भेजती है, तो राज्यपाल को तुरंत मंजूरी देनी होगी, जब तक कि विधेयक असंवैधानिक न हो। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल से विधेयकों पर समय सीमा में फैसला लेने की मांग की थी। सरकार का तर्क था कि राज्यपाल की निष्क्रियता से राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े विधेयक भी शामिल थे।

अदालत ने कहा कि राज्यपाल ऐसी कार्रवाई तभी कर सकते हैं, जब विधेयक केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक महीने में विधेयक राष्ट्रपति को भेजने या तीन महीने में असहमति का फैसला लेने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि यह समय सीमा मनमानी निष्क्रियता को रोकने के लिए जरूरी है। यह फैसला राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ईडी के रडार पर आयी केरल के मुख्यमंत्री विजयन की बेटी वीना

न्यूज़ डेस्क

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी वीना की मुश्किलें अब बढ़ सकती है क्योंकि वह ईडी के रडार पर आ गई है। माना जा रहा है कि अगर जांच आगे बढ़ेगी तो सीएम विजयन की मोइश्किले भी बढ़ सकती है। हालांकि सीएम विजयन ने कहा है कि जिस मुद्दे को लेकर जांच की बात की जा रही है वह सब बेकार है और जो भी हुआ है वह लीगल तरीके से हुआ है। बता दें कि वीना के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की तैयारी में है और इसको लेकर केरल की राजनीति गर्म हो गई है।

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि न तो वह और न ही उनकी पार्टी 'अवैध भुगतान' घोटाले में उनकी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की कार्रवाई को गंभीरता से ले रही है और इससे उन पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। विजयन ने कहा कि उन्हें पता है कि इस कदम के पीछे की मंशा उन्हें निशाना बनाना है। दरअसल वीना 2023 के आयकर मामले के बाद अलग-अलग केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं। इसके अनुसार उनकी अब बंद हो चुकी सूचना प्रौद्योगिकी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2018-2019 में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि इसने कोई सेवा प्रदान नहीं की थी। इसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी वीना की फर्म के खिलाफ जांच शुरू की। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने एसएफआईओ जांच को चुनौती देने वाली एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

पिछले सप्ताह केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कोच्चि की एक अदालत में

एसएफआईओ की ओर से दायर आरोपपत्र के बाद वीना के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही को मंजूरी दे दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने मामले में केस के कागजात मांगने के लिए एसएफआईओ को पत्र लिखा है। एसएफआईओ की ओर से अपने आरोपपत्र में लगाए गए आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अंतर्गत आते हैं। हम कागजात की जांच करेंगे और फिर मामला दर्ज करेंगे।

केरल के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की ओर से इस संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि मैं जानता हूं कि आपको मेरा खून चाहिए, लेकिन यह आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आप मेरे इस्तीफे की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसएफआईओ का मामला अदालत में है और इसे कानूनी तरीके से निपटाया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता विजयन की यह टिप्पणी इन खबरों के बीच आई है कि प्रवर्तन निदेशालय उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहा है, जो कथित 'अवैध भुगतान' घोटाले में पहले ही एसएफआईओ की जांच का सामना कर रही हैं।

वक्फ कानून के बाद कैसी होगी जाटलैंड की राजनीति ?

राजनीतिक डेस्क

मुसलमानो की राजनीति करने वाली अधिकतर एनडीए की पार्टियां वक्फ कानून बनने के बाद फंस गई है। एनडीए के साथ हर राज्य में कई ऐसी पार्टियां है जो मुस्लिम वोट बैंक राजनीति करती है लेकिन अब उसकी राजनीति कहाँ तक चलेगी यह देखना बाकी है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलडी भी है। राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी है और अब इस पार्टी का सञ्चालन उनके पुत्र चौधरी करते हैं। पश्चिम यूपी में इस पार्टी की काफी पकड़ है और इस पार्टी को जाट और मुसलमानो का भरपूर समर्थन मिलता रहा है। जाट और मुस्लिम समीकरण पर रालोद की राजनीति चलती है और यह पार्टी हर चुनाव में कुछ सीटें जरूर जीत जाती है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव रालोद की राजनीति चलती रहती है और इस पार्टी के लोग चुनाव जीतते रहते हैं। लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद जाटलैंड की यह पार्टी अब फंसती जा रही है। जिस तरह इस पार्टी से मुसलमान नेताओं का बाहर निकलना जारी है उससे तो यही लगता है कि रलोग किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ती जा रही है।

बता दें कि यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी सिर्फ अपने-अपने समुदायों प्लस मुस्लिम वोटों के इर्द-गिर्द पूरी राजनीति करते हैं। मसलन सपा के साथ यादव और मुस्लिम गठजोड़, बसपा के साथ दलित और मुस्लिम गठजोड़ और आरएलडी के साथ जाट और मुस्लिम गठजोड़ अभी तक काम करते रहे हैं। आरएलडी पूरी तरह से पश्चिमी यूपी आधारित पार्टी है। जयंत पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और अजीत सिंह के बेटे।

यूपी में सपा, आरएलडी और बसपा से अगर कोई एक समुदाय छिटक जाए तो उस पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ जाता है। पश्चिमी यूपी में जैसे ही आरएलडी मुस्लिमों के छिटकने से कमजोर पड़ेगी। बीजेपी उसकी जगह ले लेगी। बीजेपी का यह प्रयोग तमाम राज्यों में जारी है। बिहार उसका ताजा उदाहरण है। जहां बीजेपी ने जेडीयू को एक तरह से प्रभावहीन कर दिया है। पार्टी के कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं, जैसे प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी और हापुड़ के जिला महासचिव मोहम्मद जकी, ने इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों ने आरएलडी की राजनीतिक रणनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके आधार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वक्फ कानून जिसे केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद में पारित किया, मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद का विषय बन गया है। इस बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और नेता इसे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्तियों पर हमले के तौर पर मानते हैं। आरएलडी, जो एनडीए का हिस्सा है, ने इस बिल का समर्थन किया। जयंत चौधरी के इस फैसले से पार्टी के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप शाहजेब रिजवी और मोहम्मद जकी जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी।

हालांकि जिला स्तर पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की तादाद कहीं ज्यादा है। आमतौर पर पश्चिमी यूपी के मुसलमान राजनीतिक तौर पर राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन और आरएलडी से जुड़े हैं। दूसरे नंबर पर सपा और कांग्रेस है। राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की ही पार्टी को समर्थन करते हैं।

शाहजेब रिजवी ने अपने इस्तीफे में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की 10 विधानसभा सीटों की जीत में मुस्लिम वोटों का बड़ा योगदान था, लेकिन जयंत चौधरी ने इस समुदाय के साथ "विश्वासघात" किया। इसी तरह, मोहम्मद जकी ने पार्टी पर मुस्लिम और वंचित समुदायों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इन नेताओं का मानना है कि जयंत सत्ता की लालच में अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की राजनीति पारंपरिक रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के समर्थन पर टिकी रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 32% है और जाट समुदाय भी प्रभावशाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन कर 8 सीटें जीती थीं, जिसमें मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका थी। हालांकि, 2024 में भाजपा के साथ गठबंधन और अब वक्फ बिल के समर्थन ने इस सामाजिक समीकरण को खतरे में डाल दिया है।मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे से यह संकेत मिलता है कि आरएलडी का मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हो सकता है। पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और बागपत, पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन इस्तीफों से न केवल पार्टी की आंतरिक एकता प्रभावित होगी, बल्कि इसका असर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।

आखिर अखिलेश मीडिया से क्यों हैं नाराज?

न्यूज़ डेस्क

भाजपा के समर्थन में काम कर रहे देश के कुछ मीडिया संस्थानों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासे नाराज चल रहे हैं। एक तरफ वे बीजेपी से लड़ते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ वे अब कई मीडिया संस्थानों को भी रडार पर ले रहे हैं। यादव ने प्रदेश से निकलने वाले जगन अखबार और न्यूज़ 24 चैनल से काफी नाराज लग रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों और नेताओं को साफ़ तौर पर कह दिया है कि वे जागरण अखबार को न पढ़े और न ही न्यूज़ 24 के डेबिट में जाए क्योंकि ये दोनों सपा और सपा प्रमुख के खिलाफ एक नैरेटिव चला रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं।

बता दें कि अखबार के बारे में तो हर कोई जनता है कि यह बीजेपी और संघ के समर्थन में काम करता है लेकिन आश्चर्य की है कि जिस न्यूज़ 24 चैनल से अखिलेश यादव नाराज है वह कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल की पत्नी अनुराधा प्रसाद चलाती है। अनुराधा प्रसाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की बहन है। कायदे से इस चैनल को अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं होना चाहिए लेकिन अखिलेश यादव काफी नाराज हो

गए हैं। अब समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि उनके कोई भी नेता अब न्यूज़ 24 के डेबिट में नहीं जायेंगे। सपा का कहना है कि ये सब झूठा नरेटिव चलते हैं और बदनाम करते हैं। जिस बात से बीजेपी को लाभ हो वही काम ये चैनल करते हैं।

असल में अखिलेश इस बात से नाराज हैं कि 'दैनिक जागरण' ने उनको लेकर एक धारणा बनाई जिसे दूसरे मीडिया समूहों में प्रचारित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिस समय अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हुए उस समय इस अखबार ने प्रचारित किया कि मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए अखिलेश और उनके परिवार के लोग नल की टोंटी भी खोल ले गए। उसके बाद भाजपा के इकोसिस्टम ने अखिलेश के लिए 'टोंटी चोर' का जुमला प्रचारित किया। सोशल मीडिया में आज भी यह बात प्रचारित होती है। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है। बंगले का रखरखाव करने वाली एजेंसी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है और न कोई शिकायत दर्ज की गई लेकिन अखिलेश के बारे में एक नकारात्मक धारणा बना दी गई। इस बात को लेकर सपा के प्रवक्ता कई बार टेलीविजन चैनलों पर भाजपा प्रवक्ताओं और एंकर्स से लड़ चुके हैं।

अब यही बात फिर से 'न्यूज 24' के एक प्रोग्राम में दोहराई गई। हालांकि एंकर ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसने अखिलेश यादव के बारे में पूछा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'टोंटी चोर' का जुमला बोला। इसका कोई प्रतिवाद एंकर ने नहीं किया। अखिलेश और उनकी पार्टी इस बात से बहुत नाराज है। ध्यान रहे कोई दो दशक पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के बारे में भी इस अखबार ने आपत्तिजनक टिप्पणी छापी थी, जिसके बाद बसपा नेताओं ने इस अखबार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान चलाया था।

क्या है कानपुर के विकास को लेकर योगी सरकार का नया मास्टर प्लान?

कानपुर क्षेत्र के परिसीमन के साथ ही आठ जिलों को शामिल करके दिल्ली-एनसीआर के तर्ज पर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी के निर्धारण के कार्य को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान-2051 के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।

न्यूज़ डेस्क

लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड विकसित कर रही योगी सरकार कानपुर व आसपास के कई जिलों को जोड़ते हुए विशेष क्षेत्र बनाएगी। प्रदेश सरकार दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर कानपुर समेत 8 पड़ोसी जिलों का विकास करेगी। योजना के मुताबिक प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक शहर कानपुर समेत उसके पड़ोसी जिलों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाएगा। इसके मद्देनजर कानपुर विकास प्राधिकरण ने जीआईएस आधारित मास्टर प्लान-2051 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रक्रिया के तहत बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज तथा कानपुर नगर व देहात के कुल 20,094 किमी वर्ग क्षेत्र में विकासपरक योजनाओं को गति देने के लिए कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी यानी क्रीडा का निर्धारण किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास के साथ ही इस क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने वाला कदम साबित होगा। केडीए अधिकारियों का कहना है कि कानपुर की पहचान न केवल प्रदेश बल्कि देश के पुराने व प्रतिष्ठित औद्योगिक शहरों में शामिल नगर की रही है। इसके बावजूद, कानपुर व उसके आसपास के जिलों में असंतुलित शहरी विकास की समस्या देखने को मिलती है।

इसी कड़ी में, कानपुर क्षेत्र के परिसीमन के साथ ही आठ जिलों को शामिल करके दिल्ली-एनसीआर के तर्ज पर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी के निर्धारण के कार्य को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मास्टर प्लान-2051 के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। मास्टर प्लान-2051, कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी के क्रियान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार करने पर फोकस है जो क्षेत्र में भूमि उपयोग के नियंत्रण तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियों का प्रावधान करने में मददगार होगी।

अधिकारियों ने बताया कि इससे नगर विकास, औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय-अनावासीय संरचनाओं के निर्माण समेत भविष्य की जरूरतों के अनुसार सभी संसाधनों के विकास, संचालन व प्रबंधन की प्रक्रिया को बल मिलेगा। इस काम को पूरा करने के लिए विशिष्ट टीम की तैनाती होगी जिसकी प्रक्रिया जारी है।

नयी खोज से मिलेगी लोगों को गंजेपन से राहत

हेल्थ डेस्क

सिंगापुर में ड्यूक-एनयूएस मेडिकल स्कूल और ऑस्ट्रेलिया में वाल्टर और एलिजा हॉल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक टीम के नेतृत्व में एक अध्ययन किया गया है जिसमे वैज्ञानिकों ने एमसीएल-1 नामक प्रोटीन का पता लगाया है, जिसकी बालों के विकास और हेयर फॉलिकल (रोम) को सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर इस प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए तो न सिर्फ बालों को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि इससे गंजेपन के जोखिमों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। चूहों पर किए गए अध्ययन में अच्छे परिणाम देखे गए हैं। अध्ययन को नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

इस प्रोटीन की बालों के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, इसे समझने के लिए टीम ने चूहों में 90 दिनों के लिए इस प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया, प्रोटीन ब्लॉक होने के बाद चूहों के बाल तेजी से झड़ने लगे। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये प्रोटीन बालों के विकास के लिए जरूरी है। यह हेयर फॉलिकल स्टेम

सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है। एमसीएल-1 प्रोटीन फॉलिकल स्टेम सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। अगर इस प्रोटीन को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं या इसके लिए कोई दवा विकसित कर ली जाए तो इससे बालों का दोबारा उगना आसान होता है।चूहों के बाद अब इंसानों पर इसका परीक्षण किया जाना है।

कुछ दशकों पहले तक माना जाता था कि उम्र बढ़ने के साथ बालों के सफेद होने या झड़ने की दिक्कत बढ़ जाती है। 50 की उम्र के बाद गंजेपन का खतरा अधिक होता है, हालांकि ये अब बीती हुई बातें होकर रह गई हैं। आज के समय में 20 से भी कम उम्र के लोग बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान देखे जा रहे हैं। 20-30 की उम्र वाले लोगों के न सिर्फ तेजी से बाल झड़ रहे हैं, इनमें गंजेपन की दिक्कत भी बढ़ गई है। लेकिन अब इस नए अध्ययन से दावा किया जा रहा है कि इससे न सिर्फ बालों को गिरने से रोका जा सकता है साथ ही नए बालों को उगाना भी आसान हो सकता है।एक डेटा के अनुसार भारत में 25 से कम आयु के लगभग 50.31% पुरुष बाल झड़ने या गंजेपन की समस्या से परेशान हैं, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों में ये आंकड़ा 25.89% है। बालों के इलाज या फिर इसे दोबारा उगाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर अकेले भारत में हर साल 2500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हो रहा है।

वैज्ञानिकों की एक टीम बालों की इन समस्याओं का स्थायी इलाज ढूंढने की दिशा में काम कर रही है जिन्हें शुरुआती स्तर पर सफलता मिलने की खबर है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन की रिपोर्ट में लिखा, यह पहले से ही ज्ञात था कि एमसीएल-1 कई अलग-अलग प्रकार के ऊतकों को डेड होने से बचाने में मददगार है। जब बालों की बात आती है, तो एमसीएल-1हेयर फॉलिकल को भी क्षतिग्रस्त होने से बचा सकता है।इंसानों पर अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो ये बालों की बढ़ती समस्या के इलाज में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एमसीएल-1 प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाना देने वाली दवाओं या अन्य माध्यम से बालों का इलाज करना और गंजेपन को कम करना आसान हो सकता है।

हर महिलाओं को मैमोग्राफी करानी चाहिए ताकि स्तन कैंसर का पता चले

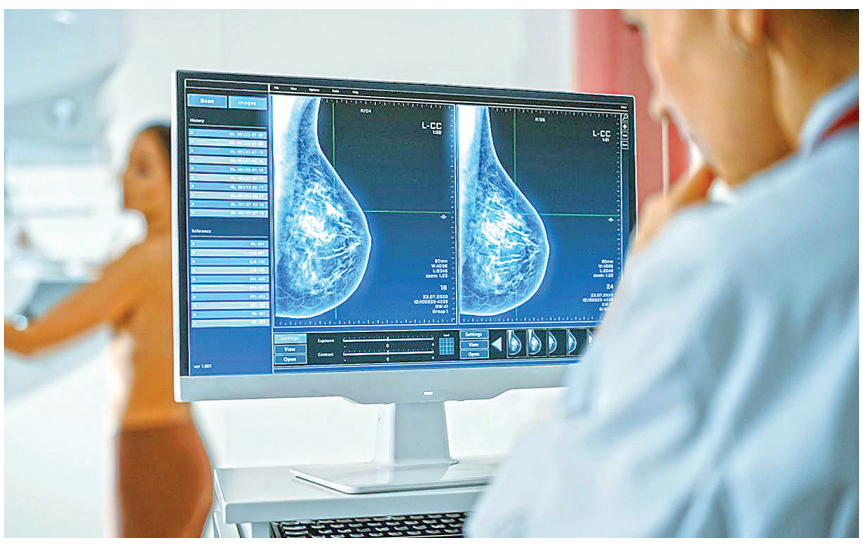

हेल्थ डेस्क

अगर समय रहते कैंसर की जांच कर इलाज हो जाए तो मरीजों की जान बचने की काफी संभावना रहती है, लेकिन एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की 100 महिलाओं में से केवल महिला स्तन कैंसर की जांच कराती हैयह अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं में मुंबई और वाराणसी स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ता भी शामिल हैं। यह अध्ययन बायोमेड सेंट्रल (बीएमसी) पब्लिक हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत में मैमोग्राफी की दर दुनियाभर की तुलना में बहुत कम हैं। अफ्रीकी देशों में मैमोग्राफी दर 4.5 प्रतिशत, कोरिया और जापान जैसे एशियाई देशों में 40-60 प्रतिशत, तथा यूरोप और अमेरिका में 84 प्रतिशत है। मैमोग्राफी एक्स-रे इमेजिंग टेस्ट है, जिससे स्तन की जांच की जाती है।

मैमोग्राफी स्तन कैंसर और दूसरे स्तन रोगों का पता लगाने में मदद करता है। देश में राज्यों के बीच मैमोग्राफी की दर में काफी असमानता है। केरल में

45 वर्ष और उससे अधिक आयु की भारतीय महिलाओं में मैमोग्राफी का दर 1.3 प्रतिशत था, 45-59 वर्ष की आयु में 1.7 प्रतिशत और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में 0.9 प्रतिशत था।

जहां मैमोग्राफी दर सबसे अधिक 4.5 प्रतिशत है, वहीं नगालैंड में यह शून्य प्रतिशत दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश में मैमोग्राफी दर 0.1 प्रतिशत, उत्तराखंड में 0.27 प्रतिशत है। कर्नाटक में मैमोग्राफी दर 2.9 प्रतिशत है। अध्ययन के लिए टीम ने 35 हजार से अधिक महिलाओं के डाटा का विश्लेषण किया। सर्वेक्षण 2017-18 में आयोजित किया गया था। विश्लेषण से पता चला कि 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की भारतीय महिलाओं में मैमोग्राफी का दर 1.3 प्रतिशत था, 45-59 वर्ष की आयु में 1.7 प्रतिशत और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में 0.9 प्रतिशत था।

दस मिनट की साइकिलिंग से हार्ट और फेफड़े रहेंगे स्वस्थ

साइकिल चलाने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में कारगर हो सकता है। दरअसल, सुबह की ताजी हवा में साइकिलिंग करने से मानसिक शांति मिलती है।

हेल्थ डेस्क

सेहतमंद रहना है तो रोजाना सुबह वॉक, जॉगिंग या साइकिल जरूर चलाना चाहिए। अगर आप दस मिनट रोज साइकलिंग करते हैं तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपको हार्ट और फेफड़े की शिकायत नहीं होगी। इसके साथ ही आपकी सेहत में कई और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साइकिल चलाने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है।इसके साथ ही अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको साइकिल जरूर चलाना चाहिए। आप रोजाना 10 मिनट की साइकिलिंग करें। ये भी कारगर हो सकती है। इससे कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है।

साइकिल चलाने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में कारगर हो सकता है। दरअसल, सुबह की ताजी हवा में साइकिलिंग करने से मानसिक शांति मिलती है। आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करते हैं।जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आपकी सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है। यह फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन लेने और शरीर में सही तरीके से पहुंचाने में मदद करता है।

इसके साथ ही अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। आपको बता दें कि साइकिल चलाने से प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। अगर छोटी दूरी के लिए साइकिल से जाया जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकता है।अगर आप अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रोज साइकिलिंग करना चाहिए। इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। यह अनिद्रा की समस्या को दूर करने में सहायक होता है।

सुपारी की खेती से होगी लाखों की कमाई

कृषि डेस्क

सुपारी की खेती से भी देश के किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों को सुपारी की खेती करने में दिलचस्पी है ,वे इस खेती को आगे बढ़ा सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। सुपारी का पेड़ लम्बे समय तक फल देता है और अच्छी कमाई भी लम्बे समय तक होती रहती है।

विश्वभर में भारत सुपारी उत्पादन में सबसे आगे हैं। देश के कर्नाटक, केरल, असम और पं. बंगाल में सुपारी उत्पादन 85 प्रतिशत किया जाता है। इसका इस्तेमाल भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों पूजा विधि के अलावा अन्य कार्यो में किया जाता है। आजकल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पान मशाला में किया जाता है। सुपारी की महिलाओं के ल्यूकोरिया इलाज में भी मददगार होता है। देश में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू में सुपारी का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक बार खेती करने पर 70 साल तक पैदावार होती है। देश में सुपारी की कीमत 450 से 600 रूपये किलो बताई जाती है। किसान सुपारी की खेती कर लाखों का मुनाफा कमाते हैं।

ऐसे करें खेती

सुपारी की खेती के लिए लाल मिट्टी, दोमट लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए सुपारी के बीज से पौधे को नर्सरी तकनीक में तैयार किया जाता है। पौधा तैयार होने के लिए आंशिक रूप से धूप की आवश्यकता होती है। इसके रोपण में 15 से 18 माह का समय लग जाता है। रोपाई वर्षा ऋतु के जुलाई माह में की जाती है। रोपाई में एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2.7 मीटर पर की जानी चाहिए। इसके अनुसार एक एकड़ में 400 पौधा रोपड़ किया जाता है। सुपारी का पेड़ नारियल की तरह चौड़े पत्तों में 50 से 70 फिट लंबा होता है। तैयार होने के लिए तापमान 18 से 26 अनुकूल माना जाता है औऱ मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच होना उपयुक्त होता है।

कैसे करें रखरखाव

सुपारी का पौधा फलदार वृक्ष बनने के लिए 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं। इसकी सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होता है। सालभर में 6 माह तक एक पौधे को 15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। रोपण किये गए खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव होने पर छोटी-छोटी नाली बनाकर पानी खेत से बाहर निकालना अनिवार्य है। पौधे से अच्छा पैदावार होने के लिए गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद का उपयोग करना जरूरी है।

सुपारी खाने के लाभ

सुपारी खाने से कई बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे औषधीय के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका सेवन करने से दस्त, पाचन, कब्ज और एनीमिया, मुहं के छाले और पेट से जुड़ी कई बीमारियों में आराम मिलता है। बावासीर की समस्या होने में सुपारी का पानी पीने से बहुत लाभ होता है। सुपारी में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो पेट व आंतों की प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। चेचक की बीमारी में 1-2 ग्राम सुपारी के चूर्ण को लगातार पानी में घोलकर पीने से निजात पाया जा सकता है। महिलाओं के लिए सुपारी का उपयोग प्रसवोत्तर समस्याओं के साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याओं में फायदेमंद है। यह ल्यूकोरिया और पेट संबंधित बीमारियों में राहत देता है।

लाखों में कमाएं मुनाफा

सुपारी के पौधे में 5 से 8 वर्ष में पैदावार शुरू हो जाती है। इसकी तोड़ाई तीन-चौथाई भाग पक जाने पर की जाती है। सालभर में एक पेड़ से 15 से 30 किलो के आसपास सुपारी उत्पादन होता है, जो एक बार लगाने पर 70 साल तक उत्पादन करता है। बाजार में सुपारी की कीमत 400 से 600 रूपये किलो बेची जाती है। इसे अधिक कीमत में बेचने के लिए कंपनी ट्रेडमार्क से टायप कर या ऑनलाईन शॉपिंग में बेचा जा सकता है। लोग एक बार इसकी खेती कर कई साल तक लाखों में कमाई कर सकते हैं।

मालाबार नीम की लकड़ी से करोडो की कमाई संभव

कृषि डेस्क

अगर किसान व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो उन्हें मालाबार पेड़ लगाने की शुरुआत करनी चाहिए। इस पेड़ की लकड़ी से कई कीमती सामन बनती है और ये लकड़ी काफी महँगी भी होती है। किसान इस लकड़ी वाले पेड़ की खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। मालाबार नीम की खेती किसानो को करोड़पति बना सकती है। मालाबार नीम को मेलिया डबिया भी कहा जाता है। इसके पेड़ आप फसलों के साथ भी लगा सकते हैं।

केवल 5 साल के अंदर ही आप इनके जरिए करोड़पति बन सकते हैं। मालाबार नीम की लकड़ी का इस्तेमाल माचिस की तीली बनाने, सोफा-कुर्सी बनाने, पैकिंग के समान बनाने जैसे कई उपयोगी चीजों के लिए किया जाता है। बता दें कि यह साधारण नीम से थोड़ा अलग होता है। इसे आप खेतों के आसपास लगा सकते हैं और इसके लिए ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसे लगाने के लिए मार्च से अप्रैल का महीना सही माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सभी प्रकार की मिट्टी में इसे लगाया जा सकता है।

लगभग चार एकड़ खेत में 5000 के आसपास पेड़ लगाए जा सकते हैं। इन पेड़ों के बीच में आप किसी फसल को भी लगा सकते हैं। 5000 पेड़ों में से लगभग 2000 पेड़ आप खेत की बाहरी मेड पर लगा सकते हैं और इसके अलावा बाकी के पेड़ अंदर लगा सकते हैं। केवल 2 साल में ही यह पेड़ 40 फीट तक ऊंचे हो जाते हैं। 5 साल में इन पेड़ों से इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। इन पौधों के ज्यादा डिमांड में रहने की खास बात यह भी है कि इनमें दीमक नहीं लगती है। प्लाईवुड उद्योग में इस लकड़ी की ज्यादा मांग है। इसलिए इसकी खेती करने वाले हमेशा मुनाफे में रहते हैं। पेड़ लगाने के लगभग 5 साल बाद प्लाईवुड और लगभग 8 साल बाद इन लड़कियों से फर्नीचर तक बनाया जा सकता है। जितनी ज्यादा इन पेड़ों की उम्र होती है उतना ही ज्यादा इसे पैसा कमाया जा सकता है। यदि आप लगभग 4 एकड़ खेत में मालाबार नीम के पेड़ों को लगाते हैं तो इससे आप लगभग 50 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। जो बड़े किसान हैं वे ज्यादा खेती करके करोड़ों की कमाई भी कर सकते हैं।

जैव विविधता का प्रतीक हैं बुरांश के फूल

न्यूज़ डेस्क

उत्तराखंड के पहाड़ों में बुरांश के फूल खिल चुके हैं। इस फूल के खिलने का इन्तजार आम लोगों को तो रहती ही है ,पर्यटकों को भी ये फूल खूब भाते हैं। इस फूल के खिलते ही लोग मान लेते हैं कि मौसम में बदलाव हो गए हैं और ऋतू परिवर्तन भी हो गए हैं। उत्तराखंड में बुरांश का वृक्ष राजकीय वृक्ष घोषित है। मार्च और अप्रैल के महीने में जब हिमालयी इलाकों की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं, तब निचले इलाकों में बुरांश के फूल खिलकर पहाड़ों को एक अद्भुत प्राकृतिक श्रृंगार देते हैं। इसे उत्तराखंड की जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। इसके फूलों से बना जूस स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

कई गुणों से समाहित ये फूल बेहद पवित्र होने के साथ ही एक तरफ खिलकर जंगलों में लालिमा फैलाता है वहीं शरीर के लिए भी लाभदायक है। बुरांश की चाय, स्क्वैश और तमाम तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बुरांश की छटा देखने के लिए उत्सुक रहता है। जब पहाड़ के जंगलों में बुरांश के पेड़ लाल फूलों से भर जाते हैं, तो यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगत। यही कारण है कि बुरांश का खिलना सिर्फ एक ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि हर पहाड़ी के लिए एक उत्सव जैसा होता है। बुरांश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके फूलों से बना जूस हृदय रोगों से बचाव, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि पहाड़ों में लोग इसे पारंपरिक औषधि की तरह भी इस्तेमाल करते हैं।

उत्तराखंड की जैव विविधता में बुरांश का विशेष स्थान है यह न सिर्फ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है. हर साल सैकड़ों पर्यटक बुरांश के फूलों से सजे जंगलों को देखने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों का रुख करते हैं। स्थानीय लोकगीतों और कहानियों में बुरांश का खास जिक्र मिलता है। उत्तराखंड के लोग इसे सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं।

'कम खर्च में लेमन ग्रास की खेती से भरी मुनाफा

कृषि डेस्क

लेमन ग्रास की खेती मात्र 20 हजार रुपये में शुरू किया जा सकता है। इसे करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है।लेमन ग्रास की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसका तेल निकाला जाता है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक, साबुन, तेल और दवा बनाने में किया जाता है। काफी कंपनियां किसानों से सीधा कॉन्टेक्ट करके लेमन ग्रास खरीद लेती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे सूखा प्रभावित इलाकों में भी लगाया जा सकता है। एक हेक्टेयर में इसकी खेती करके सालभर में करीब 4 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं। लेमन ग्रास की खेती का सबसे बड़ा एक फायदा यह भी है कि इसे जंगली जानवर नष्ट नहीं करते।

अगर आपके पास एक हेक्टेयर जमीन है तो आपको लेमन ग्रास की खेती करने के लिए शुरू में 20 से 40 हजार रुपये निवेश करने होंगे। इसे शुरू करने का सबसे सही समय फरवरी का महीना माना जाता है। एक बार लगाने के बाद इसकी 6 से 7 बार कटाई कर सकते हैं। अगर आप एक हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती करते हैं तो इससे आप साल भर में 325 लीटर तेल निकाल सकते हैं। मार्केट में एक लीटर तेल की कीमत करीब 1000 रुपये से 1500 रुपये है। इस प्रकार आप एक साल में 3 लाख रुपये से 4 लाख रुपये या इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। एक हेक्टेयर खेत में पूरे साल 5 टन लेमन ग्रास की खेती की जा सकती है।

चीन -अमेरिका ताइवान को लेकर आमने -सामने

इंटरनेशनल डेस्क

अमेरिकी ख़ुफ़िया रिपोर्ट के खुलासे से पता चलता है कि चीन बहुत जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। और ऐसा हुआ तो चीन के खिलाफ अमेरिका मैदान में उतरेगा। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में एशिया में युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती है अजर फिर कई देश इसमें गतबाह हो सकरते हैं। अमेरिकी ख़ुफ़िया रिपोर्ट की माने तो चीन जल्दी ही ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि उनका मानना है कि चीनकी ओर से ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास छह महीने से कम समय में हो सकता है। इससे चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष की शुरुआत हो सकती है।

ख़ुफ़िया सूत्रों के आधार पर 19 फोर्टी फाइव ने दावा किया है कि चीन की ओर से ताइवान पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। चीन ने इसके लिए तैयारी कर ली है और इसी साल ये हमला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अगले छह महीनों में ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये ऐसा समय हो रहा है जब चीनी सत्ता के गलियारों में ताइवान पर हमले की मांग बढ़ रही है। बीजिंग में सवाल हो रहा है कि अगर ताइवान को अब नहीं तो कब चीन का हिस्सा बनाया जाएगा।

अमेरिका ने लगातार ताइवान को अपना समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मानते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान पर चीनी आक्रमण को रोकना मुमकिन नहीं होगा। चीनी सेना और सरकार ताइवान को अपने में मिलाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें नाकाबंदी, सैन्य हमले और दूसरे

विकल्प शामिल हैं। चीन, ताइवान के साथ जो कर रहा है उसमें इंटरनेट और संचार के केबलों को काटना, चुनावों में हस्तक्षेप करना और गलत सूचनाएं फैलाना शामिल है। सूत्रों का ये भी मानना है कि अमेरिका इसमें दखल से सकता है और चीन की ये कोशिश ताइवान में बड़ी जंग की वजह बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुऐ है। चीन इस समय को ताइवान पर कब्जा करने के लिए सटीक मान रहा है। चीन अगले छह महीनों में ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और कैलिफोर्निया के पूर्व लॉ मेकर चक डेवोरे ने तीन संभावित तरीके बताए हैं। इसमें धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना, अचानक बड़ा हमला और गलत सूचनाओं से अराजकता फैलाना है।

डेवोरे के अनुसार, पहला विकल्प ताइवान की पूरी तरह से नाकाबंदी करना होगा। इसमें चीन की नौसेना ताइवान को चारों तरफ से घेर लेगी। इससे ताइवान का जलमार्ग एक 'किल जोन' बन जाएगा। ताइवान अपनी जरूरत का 90 फीसदी खाना और 100 फीसदी प्राकृतिक गैस जहाजों से मंगवाता है। ऐसे में चीन की नाकाबंदी से ताइवान किसी भी शर्त को मानने के लिए बेबस हो जाएगा। इस तरह चीन को ताइवान को झुकाने के लिए किसी बड़े आक्रमण की जरूरत नहीं होगी।

चीन का दूसरा विकल्प ताइवान पर मिसाइलों से हमला करना है। इससे ताइवान के सुरक्षा तंत्र को भारी नुकसान होगा। ताइवान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे। चीन क हैकर्स ताइवान के पावर ग्रिड को क्रैश कर देंगे और इंटरनेट और फोन नेटवर्क को बंद कर देंगे। इसके साथ ही चीन के 1,00,000 सैनिक ताइवान के तटों पर हमला कर देंगे। चीन का लक्ष्य होगा कि कुछ ही दिनों में ताइपे पर कब्जा कर लिया जाएगा।

चीन का तीसरा विकल्प सबसे खतरनाक हो सकता है इसमें ताइवान पर कब्जा करने के साथ-साथ चीन की ओर से अमेरिका और उसके सहयोगियों की रक्षा क्षमता को नष्ट करने की कोशिश करेगा। चीनी मिसाइल हमले ना केवल ताइवान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे, बल्कि जापान, गुआम और फिलीपींस में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे।

रिपोर्ट कहती है कि चीन इनमें से कौन सा विकल्प चुनेगा, यह कहना मुश्किल है लेकिन यह तय है कि चीन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने हालिया वक्त में लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास भी किए हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वह ये तय कर चुका होगा कि कैसे ताइवान को चीन में मिलाने के लिए आक्रमण करना होगा।

आखिर तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव क्यों बढ़ रहे हैं?

इंटरनेशनल डेस्क

इसी सप्ताह के अंत तक अमेरिका और ईरान केर बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसके लिए अमेरिका ने ईरान को पत्र भी लिखा है। लेकिन बैठक से पहले ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गए हैं। ओमान सल्तनत में बैठक से पहले जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उससे बैठक की सार्थकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान तेजी से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है जबकि इरना कहता है कि वह वही कर रहा है जो जरुरी है। लेकिन अमेरिका को यह सब पसंद नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोर देकर कहते हैं कि वे सीधी वार्ता करेंगे। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वे मध्यस्थ के माध्यम से अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन यह मायने रखता है। 2018 में विश्व शक्तियों के साथ तेहरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को एकतरफा वापस लेने के बाद से अप्रत्यक्ष वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है। ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने फिर से सुझाव दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। हालाँकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें विश्वास है कि ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर एक नया समझौता किया जा सकता है। उधर खामेनेई ने चेतावनी दी है कि तेहरान किसी भी हमले का जवाब अपने हमले से देगा।

ट्रंप ने पत्र क्यों लिखा?

ट्रंप ने 5 मार्च को खामेनेई को पत्र भेजा, फिर अगले दिन एक टेलीविजन साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने इसे भेजने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहाः "मैंने उन्हें एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है, 'मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि अगर हमें सैन्य रूप से आगे बढ़ना पड़ा, तो यह एक बड़ी बात होगी।'" व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से, राष्ट्रपति प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए बातचीत के लिए जोर दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं कि इजरायल या अमेरिका द्वारा सैन्य हमला ईरानी परमाणु स्थलों को निशाना बना सकता है।बता दें कि ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल के दौरान लिखे गए पिछले पत्र पर सर्वोच्च नेता ने नाराज़गी जताई थी।लेकिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को अपने पहले कार्यकाल में लिखे गए पत्रों के कारण आमने-सामने की बैठकें हुईं, हालांकि प्योंगयांग के परमाणु बमों और महाद्वीपीय अमेरिका तक पहुँचने में सक्षम मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ।

ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि "हम बातचीत से बचते नहीं हैं; यह वादों का उल्लंघन है जिसने अब तक हमारे लिए समस्याएँ पैदा की हैं," पेजेशकियन ने कैबिनेट बैठक के दौरान टेलीविज़न पर टिप्पणी करते हुए कहा। उन्होंने यख भी कहा कि "उन्हें साबित करना होगा कि वे विश्वास बना सकते हैं।" उधर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रम्प द्वारा सैन्य कार्रवाई की धमकी को नवीनीकृत करने वाली टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सर्वोच्च नेता ने कहा, "वे शरारती कार्य करने की धमकी देते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी।" " बहुत संभव है कि बाहर से कोई परेशानी आए। हालांकि, अगर ऐसा होता है, तो उन्हें निस्संदेह एक मजबूत जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा।" ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने आगे कहा है कि "ईरान के खिलाफ राष्ट्राध्यक्ष द्वारा 'बमबारी' की खुली धमकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मूल तत्व के लिए एक चौंकाने वाला अपमान है," उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा ही लिखा है। "हिंसा से हिंसा पैदा होती है, शांति से शांति पैदा होती है। अमेरिका रास्ता चुन सकता है...; और परिणामों को स्वीकार कर सकता है।" सरकारी स्वामित्व वाले तेहरान टाइम्स अखबार ने बिना किसी स्रोत का हवाला दिए दावा किया कि ईरान ने "अमेरिका से संबंधित ठिकानों पर हमला करने की क्षमता वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं।" ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में ईरान और यमन के ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों की मारक दूरी के भीतर स्टील्थ बी-2 बमवर्षक तैनात किए हैं, जिन पर अमेरिका 15 मार्च से ही भारी बमबारी कर रहा है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पश्चिम को चिंता क्यों है?

ईरान ने दशकों से इस बात पर जोर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालाँकि, उसके अधिकारी लगातार परमाणु हथियार बनाने की धमकी दे रहे हैं। ईरान अब यूरेनियम को हथियार-ग्रेड के स्तर 60% के करीब तक समृद्ध कर रहा है, ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है। 2015 परमाणु समझौते के तहत, ईरान को 3.67% शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध करने और 300 किलोग्राम (661 पाउंड) का यूरेनियम भंडार बनाए रखने की अनुमति थी। ईरान के कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट में इसका भंडार 8,294.4 किलोग्राम (18,286 पाउंड) बताया गया है क्योंकि यह इसका एक अंश 60% शुद्धता तक समृद्ध करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान ने अभी तक हथियार कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने "ऐसी गतिविधियाँ की हैं जो उसे परमाणु उपकरण बनाने की बेहतर स्थिति में रखती हैं।" ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली लारीजानी ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में चेतावनी दी है कि उनके देश में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षणों से कोई समस्या नहीं है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या इज़राइल इस मुद्दे पर ईरान पर हमला करते हैं, तो देश के पास परमाणु हथियार विकास की ओर बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा, "अगर आप ईरान के परमाणु मुद्दे के बारे में कोई गलती करते हैं, तो आप ईरान को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि उसे खुद का बचाव करना होगा।"

दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं पैटोंगटार्न शिनावात्रा

इंटरनेशनल डेस्क

पिछले सप्ताह थाईलैंड की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा से जब प्रधानमंत्री मिल रहे थे तब देश और दुनिया की नजर इस पर लगी हुई थी। बिम्सटेक शिखर सम्मलेन के दौरान थाईलैंड की यह प्रधानमंत्री सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं की मुलाकात और बातचीत ने लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन कौन हैं पैटोंगटार्न शिनावात्रा? वे न सिर्फ थाईलैंड के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, बल्कि अपने छोटे से राजनीतिक करियर में ही देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई हैं। उनकी उम्र अभी 38 साल बतायी जा रही है। उनके पिता थाकसिन शिनावात्रा और चाची यिंगलक शिनावात्रा भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 से 4 अप्रैल, 2025 तक थाईलैंड का दौरा किया था । यह यात्रा दो दिवसीय थी और इसका मुख्य उद्देश्य 6वें बिम्सटेक यानी वे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकनोमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन में भाग लेना था, जो बैंकॉक में आयोजित हुआ। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने थाईलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाली भाषा में लिखित "वर्ल्ड त्रिपिटकः सज्झाय फोनेटिक एडिशन" भेंट की। यह खास घटना 3 अप्रैल, 2025 को बैंकॉक में पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे के दौरान हुई। त्रिपिटक, जिसे संस्कृत में त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। यह संस्करण 108 खंडों में है और इसमें पाली भाषा के 90 लाख से अधिक शब्दांशों की सटीक उच्चारण के साथ प्रस्तुति की गई है। थाईलैंड की युवा प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा आजकल काफी चर्चा में हैं। 38 साल की उम्र में वे थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनीं, जब उन्होंने 16 अगस्त, 2024 को पद संभाला। उनकी गिनती दुनिया की सबसे युवा मौजूदा महिला नेताओं में होती है, और उनकी ताजा लोकप्रियता का एक कारण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात का वायरल वीडियो भी है।

फिर चर्चा में आई हुमा कुरैशी

फ़िल्मी डेस्क

पॉपुलर वेब सीरीज 'महारानी 4' के साथ एक बार फिर से हुमा कुरैशी पर्दे पर राज करने लौट रही हैं। जब से चौथे सीजन का टीजर आया है, तब से ही फैंस इसे देखने के लिए बेताब है। टीजर में हुमा एक बार फिर ताकतवर और तेवरदार अंदाज में नजर आई। पिछली तीन सीजन की तरह इस बार भी राजनीति, संघर्ष और सत्ता की कहानी देखने को मिलेगी। चलिए आज आपको रानी भारती उर्फ हुमा की नेट वर्थ के बारे में बताते हैं। हुमा कुरैशी को सैमसंग के एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने पहली बार देखा। जिसके बाद अनुराग ने उन्हें अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर – भाग 1 के लिए साइन किया। फिल्म सुपरहिट हुई और उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस की नेट वर्थ 23 करोड़ रुपये है। वह ऐड, मॉडलिंग, वेब सीरीज और फिल्मों से कमाई करती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस प्रति फिल्म 2-3 करोड़ रुपये की फीस चार्ज करती है। इसके अलावा एक्ट्रेस इवेंट में अपनी परफॉर्मेंस और कोलोब्रेशन से भी तगड़ी कमाई करती है।

सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा सजदेह ने शादी के 24 साल बाद तलाक ले लिया था। तलाक के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलने लगीं कि सोहेल और हुमा एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।. इस मामले को लेकर इंटरनेट पर काफी चर्चा हुई, जिसके बाद हुमा मीडिया के सामने आईं। उन्होंने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि उनके और सोहेल के बीच ऐसा कुछ नहीं है।.यहां तक कि उन्होंने सोहेल को भाई जैसा बताया था। इसके बाद डेटिंग की खबरों पर विराम लग गया।

लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं ये ओटीटी फिल्मे

फ़िल्मी डेस्क

अगर आपने पंचायत देखी है और सोचा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो जरा ठहरिए. आजकल ओटीटी की दुनिया में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज मौजूद हैं, जो पंचायत जैसी रियल और देसी कहानी से कहीं आगे निकल चुकी हैं। मजेदार किरदार, दिल को छू लेने वाली कहानियां और हर एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलेगा. ये सीरीज आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर भी मजबूर करेंगी। तो आइए जानते हैं उन 7 वेब सीरीज के बारे में, जो सिर्फ शो नहीं, पूरा सिनेमाई अनुभव हैं. अगर आपको पंचायत ने बांध कर रखा था, तो ये सीरीज आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देंगी।

महारानी

अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है और पंचायत की पॉलिटिक्स वाली दुनिया अच्छी लगी थी, तो महारानी आपके लिए एकदम परफेक्ट सीरीज है। यह कहानी है रानी भारती नाम की एक आम गृहिणी की, जो हालातों के चलते अचानक बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है। उसकी जर्नी, फैसले और सिस्टम से उसकी टक्कर इस शो को बेहद दिलचस्प बनाती है। हुमा कुरैशी ने इसमें दमदार अभिनय किया है और इसे सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. यह वेब सीरीज सोनिलिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

द विचर

अब चलते हैं जरा फैंटेसी की दुनिया में, जहां द विचर आपको एक बिलकुल अलग ही जादुई सफर पर ले जाती है। यह कहानी है गेराल्ट नाम के एक ऐसे हंटर की, जो इंसानों को राक्षसों और खतरनाक जादू से बचाता है। सीरीज में दमदार एक्शन, जबरदस्त वीएफएक्स और गहरी कहानी का शानदार मेल है, जो आपको शुरू से अंत तक बांधकर रखता है। हेनरी कैविल ने गेराल्ट का किरदार निभाया है और इस सीरीज को लॉरेन श्मिट हिसरिच ने डायरेक्ट किया है। द विचर को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

द रिक्रूट

अगर आपको स्पाई और सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज पसंद हैं, तो द रिक्रूट आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। यह कहानी है एक नए सीआईए वकील की, जो एक खतरनाक मिशन में उलझ जाता है और धीरे-धीरे उसकी जिंदगी एक बड़े खेल का हिस्सा बन जाती है। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट और टर्न्स हैं, जो आपको पूरी तरह बांधे रखते हैं। इस सीरीज में नोआ सेंटीनियो ने लीड रोल निभाया है और इसे एलेक्सी हावले ने डायरेक्ट किया है। द रिक्रूट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

स्पेशल ऑप्स

अगर आपको देशभक्ति और खुफिया मिशनों वाली कहानियां पसंद हैं, तो स्पेशल ऑप्स जरूर देखनी चाहिए। ये रॉ एजेंट हिमत सिंह की एक सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कहानी है, जिसमें के.के. मेनन ने शानदार अभिनय किया है। इसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है और ये डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

द फैमिली मैन

अब लौटते हैं देसी जमीन पर, जहां द फैमिली मैन एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जो असल में सीक्रेट एजेंट होता है। मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के रोल में दमदार एक्टिंग की है। इस सीरीज को राज और डी.के. ने डायरेक्ट किया है और इसे ऐमज़ान प्राइम पर देखा जा सकता है।

गुल्लक

अब बात करते हैं देसी एहसास से भरी गुल्लक की, जो एक मिडल क्लास श्रीवास्तव परिवार की हल्की-फुल्की और दिल छूने वाली कहानी है। छोटे-छोटे झगड़े, प्यार भरे लम्हे और मजेदार किस्सों से भरी इस सीरीज को शैलेश श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है और आप इसे सोनिलिव पर देख सकते हैं।

मनी हाइस्ट

अब बात करते हैं उस सीरीज की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी प्लानिंग और मास्टरमाइंड से दीवाना बना दिया मनी हाइस्ट। यह कहानी है द प्रोफेसर और उसकी टीम की, जो एक बड़ी बैंक लूट की धमाकेदार योजना बनाते हैं। हर एपिसोड में थ्रिल और ट्विस्ट से भरपूर ये सीरीज दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखती है। अल्वारो मोर्टे ने द प्रोफेसर का किरदार निभाया है और इसे एलेक्स पिना ने डायरेक्ट किया है. मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

बॉलीवुड में भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार नहीं रहे

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाडी केदार जाधव अब राजनीति करेंगे। जानकारी के मुताबिक़ जाधव बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं।खबर के मुताबिकजाधव मुंबई में बीजेपी में शामिल होंगे इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहेंगे। हालांकि पार्टी या जाधव की ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, उनके पार्टी में औपचारिक शामिल होने की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि 3 जून 2024 को उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी, जिससे उनके दशकभर लंबे करियर का एक अध्याय समाप्त हुआ। क्रिकेट के मैदान से संन्यास लेने के बाद केदार ने कमेंटेटर की भूमिका निभाई। अब टीम इंडिया और आईपीएल के साथ मैदान पर राज करने के बाद, वह एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं।

केदार जाधव ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रवींद्र चव्हाण से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता आशीष शेलार से भी बातचीत की। तभी से केदार के भाजपा में शामिल होने की चर्चा चल रही थी। 26 मार्च 1985 को पुणे, महाराष्ट्र में जन्मे केदार महादेव जाधव ने अपने क्रिकेट करियर में एक आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी पार्ट-टाइम ऑफ स्पिनर के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एमएस धोनी की कप्तानी में भारत की वनडे टीम में डेब्यू किया और 73 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1,389 रन बनाए और 27 विकेट भी चटकाए। उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में खेली गई 120 रनों की पारी रही, जिसमें उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई थी।

पत्रकारिता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए न्यू देहली पोस्ट की शानदार प्रस्तुति अब आपके सामने है। इसमें होगी खोजी और जानबूझ कर दबाई गई ख़बरों के उद्भेदन की शानदार प्रस्तुति - न्यू दिल्ली पोस्ट प्रिंट और डिजिटल के सभी मंचो के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है :-

न्यू देहली पोस्ट
(साप्ताहिक हिंदी)

हमारे ये सभी डिजिटल मंच सभी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं। यहाँ जाकर आप ताजातरीन ख़बरों और विश्लेषण को देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं।

Website: https://newdelhipost.co.in/
: @NewDelhiPost
: https://www.facebook.com/NewDelhiPosts
: @NewDelhiPost
:newdelhipost_official

न्यू देहली पोस्ट
B-614, 6th Floor Tower B
Noida One Building
Noida Sector 62, Gautam Budh Nagar (UP)
Pin Code -201309

संपर्क करे - Email - postnewdelhi@gmail.com